<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 06/31/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 29.09.2025

<u>अंतिम जॉच परिणाम</u>
<u>मामला सं. एडी (ओआई) -29/2024</u>

विषय: तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान के मूल अथवा वहां से निर्यातित "सोडा एश" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

एफ.सं. 6/31/2024-डीजीटीआर: समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे 'एडी नियम' या 'एंटी-डंपिंग नियम' या 'नियम' भी कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. यत:, अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे आगे 'आवेदक' या 'आवेदक एसोसिएशन' कहा गया है) ने डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और जीएचसीएल लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक कंपनियां' कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष रूस, तुर्की, यूएसए और ईरान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा

गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक आवेदन प्रस्तुत किया है और पाटनरोधी लगाने का अनुरोध किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या 06/31/2024- डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2024 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके अधीन नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई ताकि उक्त संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>जाँच का इतिहास</u>

3. विभिन्न देशों द्वारा सोडा ऐश पर एंटी-डंपिंग जाँच और उपाय लागू करने का इतिहास रहा है। पहली एंटी-डंपिंग जाँच 5 जुलाई 1999 को शुरू हुई और पूरी हुई, तथा 11 जुलाई 2000 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 12/1/99-DGAD के तहत चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। ये शुल्क अधिसूचना संख्या 107/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 4 अगस्त 2000 के तहत लगाए गए।

4. इसके बाद, अंतिम निष्कर्ष संख्या जी.एस.आर. के तहत सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। 6 अक्टूबर 2009 के आदेश संख्या 725 (ई) के तहत, जिसे 5 नवंबर 2009 की अधिसूचना संख्या 122/2009-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था।

5. इसके बाद 20 अगस्त 2010 को एक पाटनरोधी जाँच शुरू की गई, जो पूरी हो गई और 17 फरवरी 2012 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2010- डीजीएडी के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका से सोडा ऐश के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। ये शुल्क 3 जुलाई 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सनसेट समीक्षा जाँच में 14 दिसंबर 2018 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/5/2017- डीजीएडी के माध्यम से इन शुल्कों को समाप्त कर दिया।

6. इसके अलावा, 10 फ़रवरी 2012 को एक एंटी-डंपिंग जाँच शुरू की गई थी, जो पूरी हो गई और तुर्की तथा रूस से सोडा ऐश के आयात पर अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/3/2011-DGAD दिनांक 9 फ़रवरी 2013 के तहत शुल्क लगाने की सिफ़ारिश की गई। ये शुल्क अधिसूचना संख्या 8/2013- सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 18 अप्रैल 2013 के तहत लगाए गए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सनसेट रिव्यू जाँच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/4/2018-DGAD दिनांक 14 मार्च 2019 के तहत इन शुल्कों को बंद कर दिया।

ग. <u>प्रक्रिया</u>

7. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में जांच की शुरूआत करते हुए दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी।

iv. प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति प्रदान की, जिन्हें संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध माना जाता है, और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई।

vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का निदेश दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते सहित, दूतावासों को भी भेजी गई।

vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।

क. अबादान सल्फ्यूरिन कंपनी

ख. कावेह सोडा केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी

ग. सेमनान सोडा ऐश कंपनी

घ. शिराज पेट्रोकेमिकल कंपनी

ङ. मेसर्स ट्रेड हाउस लिमिटेड (बश्किरियन केमिस्ट्री)

च. ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "बेरेज़्निकी सोडा वर्क्स"

छ. जेएससी बश्किरियन केमिस्ट्री

ज. एसएएसएस सोडा ऐश सेल्स एंड सर्विसेज़

झ. मेसर्स पब्लिक स्टॉक कंपनी, क्रीमिया सोडा प्लांट,

ञ. एटी सोडा

ट. सोडा सेनायी

ठ. कज़ान सोडा इलेक्ट्रिक

ड. एफडसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स

ढ. सोल्वे सोडा ऐश

ण. जनरल केमिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स

त. एएनएसएसी

थ. एफडसी कॉर्पोरेशन

द. सिनर रिसोर्सेज एलपी

ध. सिनर व्योमिंग एलएलसी

न. सिनर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन

viii. संबद्ध जाँच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके प्रतिक्रिया दी है:

क. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री" रूस

ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बश्किर सोडा कंपनी" रूस

ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बेरेज़्निकी सोडा फ़ैक्टरी" रूस

घ. डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस.

ङ. पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी

च. पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी

छ. टुट्टी डीडसीसी

ज. सिसेकैम डीआईएस टिकारेट ए.एस.

झ. तुर्किये सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलानी ए.एस.,

ञ. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफज़ेडसीओ

ट. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी

ठ. केम्पार एनर्जी पीटीई लिमिटेड

ड. हिरण्यवर्णम केमिकल्स एंड अल्कलीज़ पीटीई लिमिटेड

ढ. एडीवी इंटरनेशनल एफज़ेडसीओ

ण. एजी सिनेर इथालाटइहराकाटवे टिकारेट ए.एस.

त. ईटीआई सोडा यूरेटिमपजरलामानक्लियेइलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे तिकारेत एएस

थ. कज़ान सोडा एलेक्ट्रिकुरेटिम एएस

द. सोडा वर्ल्ड लिमिटेड

ध. जी. इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई

न. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ

प. वी.ई.आई.सी. वे डिस टिकारेट एएस

ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए प्रश्नावली भेजी।

क. गुजरात गार्जियन लिमिटेड

ख. एडवांस सर्फेक्टेंट इंडिया लिमिटेड

ग. फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड

घ. ए.आर. स्टैंचेम प्राइवेट लिमिटेड

ङ. एलेनबिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

च. हिंद सिलिकेट्स प्राइवेट लिमिटेड

छ. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड

ज. टॉरस केमिकल (प्रा.) लिमिटेड

झ. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड

ञ. किशोरसन्स डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

ट. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

ठ. जे.जे. पटेल इंडस्ट्रीज

ड. प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर

ढ. श्रीराम भारत केमिकल एंड डिटर्जेंट्स (प्रा.) लिमिटेड

ण. अलब्राइट मोरारजी एंड पंडित लिमिटेड

त. मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज

थ. एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

द. आदर्श कांच उद्योग (प्रा.) लिमिटेड, वेयर प्राइवेट लिमिटेड

ध. यू.पी. ग्लास मैन्युफैक्चर सिंडिकेट

न. प्रगति ग्लास प्राइवेट लिमिटेड

प. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

फ. गोरा मल हरि राम लिमिटेड

ब. फेना (प्रा.) लिमिटेड

भ. रोहित सर्फेक्टेंट्स (प्रा.) लिमिटेड

म. श्री यूनिकॉन ऑर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड

य. एस्ट्रल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड

कक. पोलाची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

खख. बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

गग. वसुंधरा रसायन लिमिटेड

घघ. श्री हरि इंडस्ट्रीज,

डड. पावर सोप लिमिटेड

चच. हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

छछ . शांति नाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लिमिटेड,

जज. जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड

झझ. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड

ञञ.एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

टट. एस. कुमार डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड

ठठ. मौली एक्सपोर्ट्स

x. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क. आरना इंटरनेशनल

ख. लिब्रा अल्कलीस्कीमी प्राइवेट लिमिटेड

ग. सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

घ. पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड

ङ. एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड

च. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

xi. उपर्युक्त ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के अलावा, सेंट गोबेन इंडिया और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होमकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने आयातक प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, किंतु अपने अनुरोध प्रस्तुत किए।

xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा 04 जनवरी, 2025 तक ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया गया:

क. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री" रूस

ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बश्किर सोडा कंपनी" रूस

ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी "बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री" रूस

घ. डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस.

ड़. पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी

च. पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी

छ. टुट्टी डीडसीसी

ज. सिसेकैम डीआईएस टिकारेट ए.एस.

झ. तुर्किये सिसे और कैम फैक्ट्री ए.एस.,

ञ. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ

ट. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी

ठ. केम्पार एनर्जी पीटीई लिमिटेड

ड. हिरण्यवर्णम केमिकल्स एंड अल्कलीज़ पीटीई लिमिटेड

ढ. एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ

ण. एजी सिनेर इथालाटइहराकाटवे टिकारेट ए.एस.

त. ईटीआई सोडा यूरेटिमपज़ारलामानाक्लियाटवेइलेक्ट्रिकयूरेटिम सनायीं और टिकारेट ए.एस.

थ. कज़ान सोडा इलेक्ट्रिकयूरेटिम ए.एस.

द. सोडा वर्ल्ड लिमिटेड

ध. यू जी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई

न. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ

प. डब्लू ई आई सी और डीआईएस टिकारेट ए.एस.

फ. आरना इंटरनेशनल

ब. लिब्रा अल्कलीस्कीमी प्राइवेट लिमिटेड

भ. सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

म. पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड

य. एजीआई ग्रीनपैक लिमिटेड

र. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

xiii. आवेदक ने जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 (6 महीने) की प्रस्तावित की थी, तथापि, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 (9 महीने) के रूप में अपनाई गई थी। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 30 सितंबर 2023 और जाँच की अवधि शामिल है।

xiv. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का सौदा-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अंतिम जॉच परिणामों के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने सौदा-वार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xv. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2024 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 5 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जो हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय विस्तार के बाद 29 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया। विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन के निर्माण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर, जो उस समयावधि के भीतर प्राप्त हुए थे, विचार किया गया। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर चर्चा करने के लिए 19 नवंबर 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा की। हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने 4 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी के दायरे को स्पष्ट किया।

xvi. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।

xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से भेज दें।

xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 11 अप्रैल 2025 को एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 22 जुलाई 2025 को पुन: मौखिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे 28 जुलाई 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 5 अगस्त 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

xx. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा जाएगा) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xxi. प्राधिकारी ने इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर, उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं। प्राधिकारी अंतिम जॉच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यांकित दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जॉच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेंगे।

xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक देने से मना कर दिया है या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जॉच परिणाम दर्ज किए हैं।

xxiii. इस जाँच से संबंधित आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, 21 सितंबर 2025 को संबंधित पक्षों को जारी किया गया था। इच्छुक पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 26 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष में, संबंधित पक्षों से प्राप्त अंतिम जॉच परिणाम पर, जहाँ तक प्रासंगिक पाया गया, विचार किया गया है।

xxiv. इस अधिसूचना में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और प्राधिकारी द्वारा एडी नियम, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxv. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.14 रुपये है।

घ. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

8. विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे "पीयूसी" भी कहा गया है) की जॉच शुरूआत के चरण में परिभाषा इस प्रकार थी:

"विचाराधीन उत्पाद "डिसोडियम कार्बोनेट" है, जिसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में

घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर उनके बल्क घनत्व का है। यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद मूलतः एक जैसे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

9. हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी विभिन्न टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इस पर चर्चा करने के लिए 19 नवंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं।

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राकृतिक सोडा ऐश भारत में नहीं बनाई जाती है और इसी कारण वर्तमान जाँच में प्राकृतिक सोडा ऐश को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

ii. प्राकृतिक सोडा ऐश का उत्पादन सिंथेटिक सोडा ऐश से मौलिक रूप से भिन्न विधि से उत्पादित किया जाता है, जिसमें अयस्कों के खनन और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, सिंथेटिक सोडा ऐश के उत्पादन में सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में नमक और चूने का उपयोग किया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है।

iii. सोडा ऐश के लाइट और डेंस रूपों की लागत में अंतर होता है। इसके लिए पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता होती है।

iv. लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमत में अंतर होता है। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भी इसमें अंतर किया गया है।

v. पीयूसी के सभी निर्माता आवश्यक रूप से लाइट और डेंस सोडा ऐश दोनों का उत्पादन नहीं करते हैं।

vi. डेंस सोडा ऐश का उपयोग कांच जैसे क्षेत्रों में किया जाता है जबकि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।

vii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश में भी अंतर होता है। कीमत अंतर कच्ची सामग्री की लागत के कारण होता है। इसी कारण पीसीएन पद्धति को अपनाना आवश्यक है।

viii. प्राकृतिक सोडा ऐश पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जबकि सिंथेटिक सोडा ऐश ऊर्जा गहन है और इसमें लगभग 3 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। इससे सिंथेटिक सोडा ऐश बहुत अधिक महंगा हो जाता है।

ix. पीसीएन दृष्टिकोण को नहीं अपनाने से घरेलू और आयातित उत्पाद की तुलना विकृत होने की संभावना है। प्राकृतिक सोडा ऐश को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह अलग है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं है। डेंस और लाइट तथा सिंथेटिक और प्राकृतिक सोडा ऐश के बीच सही तुलना होनी चाहिए।

x. प्राकृतिक सोडा ऐश की तुलना में सिंथेटिक सोडा ऐश की उत्पादन लागत अधिक होती है। इन्हें अलग-अलग न करने से क्षतिरहित कीमत और सामान्य मूल्य का गलत निर्धारण होगा, जिससे मार्जिन की गणना गलत हो जाएगी।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि सोडा ऐश के दोनों रूपों के स्रोत भिन्न हैं, तथापि, दोनों स्रोतों से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में कोई अंतर नहीं है।

ii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता उद्योग द्वारा इनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है।

iii. लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 5% से कम है। घरेलू उद्योग ने लाइट और डेंस सोडा ऐश की लागत में अंतर को दर्शाते हुए अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चूँकि उक्त अंतर 5% से कम है, इसलिए अलग से पीसीएन तैयार करना अनुचित होगा।

iv. डेंस सोडा ऐश और लाइट सोडा ऐश की लागत केवल इसलिए अलग-अलग रिपोर्ट की जाती है क्योंकि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (सीईटीए) में अलग-अलग अध्याय शीर्षकों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। डेंस और लाइट सोडा ऐश को विभिन्न कोडों के अंतर्गत आयात किया जा सकता है, तथापि विभिन्न कोडों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात करने से उत्पाद भिन्न नहीं हो जाते हैं।

v. प्राधिकारी ने अपनी पूर्ववर्ती जाँचों जैसे कि 17 फ़रवरी 2012 के अंतिम जॉच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी और 9 फ़रवरी 2013 के अंतिम जॉच परिणाम संख्या 14/3/2011-डीजीएडी में बार-बार यह माना है कि सोडा ऐश के दोनों रूपों की कीमत और लागत में अंतर न्यूनतम और नगण्य है। प्राधिकारी के लिए संबद्ध वस्तुओं में जाँच की अपनी पूर्ववर्ती प्रथा से अलग जाने का कोई कारण नहीं है।

vi. केवल सोडा ऐश की उत्पत्ति पीसीएन पद्धति को अपनाने का औचित्य सिद्ध करने वाला कारक नहीं हो सकती, जब संबद्ध वस्तुओं का उपयोग उनके स्रोत के बावजूद एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा हो और संबद्ध वस्तुओं का कीमत निर्धारण भी संबद्ध वस्तुओं के स्रोत के बावजूद समान रहता है।

vii. कम कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल होने का अंतर उत्पाद को अलग नहीं बनाता है। विशेष रूप से, प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश दोनों अपने भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। एडी नियमावली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के उपाय करने के लिए नहीं बनाई गई है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियमावली के तंत्र का उपयोग करना उचित नहीं है, जिनके लिए इसे नहीं बनाया गया था।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की जाने वाली सिंथेटिक सोडा ऐश आयातित प्राकृतिक सोडा ऐश के समान वस्तु है। उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। तथापि सोडा ऐश के दोनों रूपों के स्रोत अलग-अलग हैं, फिर भी, दोनों में से किसी भी स्रोत से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक गुण और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में कोई अंतर नहीं है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

12. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद रूस, तुर्की, अमेरिका और ईरान के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "डिसोडियम कार्बोनेट" है। इसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र एनए2सीओ3 है।

13. सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों

प्रकारों में अंतर उनके स्थूल घनत्व का है। लाइट और डेंस सोडा ऐश विचाराधीन उत्पाद के केवल रूप हैं और एकसमान ही हैं। इसके अलावा, यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। वर्तमान जाँच में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

14. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

15. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/अनुरोधों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करते हैं:

16. <u>प्राकृतिक सोडा ऐश को जॉच से बाहर करने का अनुरोध</u>: प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की जाँच की है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश की उत्पादन प्रक्रियाओं में एक मूलभूत अंतर है और भारतीय उत्पादक केवल सिंथेटिक सोडा ऐश का विनिर्माण करते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि सोडा ऐश की मूल उत्पत्ति मात्र किसी उत्पाद को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, न ही उसे पीसीएन अपनाने के आधार के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएँ, स्रोत के बावजूद, उपयोग में एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि दोनों अलग-अलग कच्ची सामग्री से प्राप्त होते हैं, फिर भी दोनों में समान भौतिक और तकनीकी विशेषताएँ होती हैं, इनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ये एक ही कार्य करते हैं। यह दावा किया गया है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश एक ही उत्पाद के दो वैकल्पिक स्रोत मात्र हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पाद का उत्पादन विभिन्न मार्गों से किया जा सकता है, फिर भी उनकी आवश्यक विशेषताओं, संरचना या अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह भी देखते हैं कि पूर्ववर्ती जांचों में, पीयूसी की उत्पादन प्रक्रियाओं या विनिर्माण मार्गों के आधार पर कोई अपवर्जन नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी यह जॉच परिणाम

निकालते हैं कि पीयूसी का दायरा प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश दोनों को कवर करता है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में अपने अंतिम जॉच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी दिनांक 17 फरवरी 2012 में निम्नानुसार उल्लेख किया था:

viii. प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, सीमा शुल्क वर्गीकरण और उत्पाद के कीमत निर्धारण के संदर्भ में प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल विनिर्माण के मार्गों के संदर्भ में है। तथापि, प्राधिकारी आगे नोट करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में अंतर सोडा ऐश के दो ग्रेड को असमान वस्तुओं के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकता है।

17. <u>प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दे</u>: अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राकृतिक सोडा ऐश पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है और कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि सिंथेटिक सोडा ऐश 3 गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विभिन्न कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति का आरोप उत्पाद को अलग नहीं बनाता है और प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश की परस्पर उपयोग इनकार नहीं करता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पाद सोडा ऐश का उपयोग उपभोक्ता उद्योग द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। सिंथेटिक सोडा ऐश की तुलना में प्राकृतिक सोडा ऐश के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने देश में किसी विशेष उत्पाद के उपयोग को प्रतिबंधित करने या हतोत्साहित करने या किसी विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नियामक आवश्यकता नहीं दिखाई है। व्यापार उपचारात्मक उपाय पर्यावरणीय चिंताओं के आधार पर उत्पादों में अंतर नहीं करते हैं। पाटनरोधी जांच मुख्य रूप से अनुचित व्यापार की प्रथा को दूर करने और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

18. <u>डेंस और लाइट सोडा ऐश के लिए अलग पीसीएन</u>: अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि डेंस सोडा ऐश और लाइट सोडा ऐश के बीच लागत में अंतर है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लागत में कोई भी अंतर 5% से कम है। डेंस और लाइट सोडा ऐश में लागत अंतर नहीं होने के कारण अलग पीसीएन की आवश्यकता होने संबंधी अनुरोधों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान की है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत अंतर दिखाने के लिए सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्शाती है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत अंतर 5% से कम है। वास्तव में, घरेलू उद्योग की बिक्री सूची से यह देखा गया है कि एक ही समय में विभिन्न ग्राहकों को बेचे जाने वाले लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमतों में भी काफी अंतर होता है। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ लाइट सोडा ऐश को कुछ ग्राहकों को डेंस सोडा ऐश से अधिक कीमत पर बेचा गया है। इस प्रकार, लाइट और डेंस सोडा ऐश के लिए अलग-अलग पीसीएन अपनाना अनुचित है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सोडा ऐश की पूर्ववर्ती जाँचों में इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना है कि दोनों के बीच कीमत अंतर 5% से कम है और इसके लिए अलग से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व में की गई जाँच में अपने अंतिम जॉच परिणाम संख्या 14/17/2020-डीजीएडी दिनांक 17 फ़रवरी 2012 में निम्नलिखित उल्लेख किया था:

"जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग-अलग बल्क घनत्व के कारण अलग-अलग उत्पाद हैं और ग्राहकों द्वारा इनका परस्पर उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दोनों ग्रेड की लागत और कीमत अलग-अलग हैं। प्राधिकारी ने नोट किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत और कीमत का अंतर नगण्य है (कीमत लगभग 0.23 रुपये)। इसके अलावा, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट है कि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट क्षेत्र में सबसे आम उपयोग के अलावा सोडियम लवण, कांच, सोडियम सिलिकेट, बाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट आदि के निर्माण में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार, जबकि डेंस सोडा ऐश का उपयोग मुख्य रूप से कांच के निर्माण के लिए किया

जाता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट, सिलिकेट, अल्ट्रामरीन, बाइक्रोमेट आदि के निर्माण में भी किया जा सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि सोडा के दोनों ग्रेड राख, जिसके अनेक सामान्य उपयोग हैं, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा, चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के आयात के संबंध में पहले के अंतिम जॉच परिणाम में, प्राधिकारी ने पहले ही लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय माना था।

प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि लाइट एवं डेंस सोडा ऐश में अंतर केवल बल्क घनत्व में है। लाइट एवं डेंस सोडा ऐश की उत्पाद विशेषताएँ, उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, कच्ची सामग्री, जनशक्ति, कार्य एवं उपयोग, सीमा शुल्क वर्गीकरण और कीमत निर्धारण समान हैं, तथापि डेंस सोडा ऐश के निर्माण के लिए अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना आवश्यक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्‌यपि कुछ अंतिम अनुप्रयोगों में विशेष रूप से केवल लाइट या डेंस सोडा ऐश की आवश्यकता हो सकती है, बल्क घनत्व या कुछ उपभोक्ताओं द्‌वारा लाइट एवं डेंस सोडा ऐश का परस्पर उपयोग करने में असमर्थता के कारण दोनों को असमान वस्तुएँ नहीं माना जा सकता। ये एक ही उत्पाद के दो भिन्न रूप मात्र हैं।

दोनों ग्रेडों की अलग-अलग तुलना के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ग्रेडों की अलग-अलग तुलना केवल तभी की जानी आवश्यक है जब उत्पाद की लागत या कीमत में जाँच अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से भिन्नता हो। तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि लाइट एवं डेंस सोडा ऐश में कीमत अंतर का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं है और इसलिए पाटन मार्जिन, क्षति-रहित कीमत और क्षति मार्जिन आदि को अलग-अलग निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, प्राधिकारी ने भारित औसत के आधार पर संगत गणनाएँ की हैं।"

19. इसके अतिरिक्त, तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डाइ-सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) के आयात से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच में अपने अंतिम जॉच परिणाम में, दिनांक 9 फ़रवरी 2013 को अधिसूचना संख्या 14/3/2011-डीजीएडी के अंतर्गत, प्राधिकारी ने लाइट और डेंस सोडा ऐश के संबंध में निम्नलिखित निर्धारण किया था:

"8. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग-अलग बल्क घनत्व के कारण अलग-अलग उत्पाद हैं और ग्राहकों द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जाते हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दोनों ग्रेड की लागत और कीमत अलग-अलग हैं। प्राधिकारी ने पहले केन्या, यूएसए आदि से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में पाया था कि लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत और कीमत का अंतर नगण्य है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटर्जेंट क्षेत्र में सबसे आम उपयोग के अलावा सोडियम लवण, कांच, सोडियम सिलिकेट, बाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट आदि के निर्माण में किया जा सकता है। इसी तरह, जबकि डेंस सोडा ऐश का उपयोग मुख्य रूप से कांच के निर्माण के लिए किया जाता है, इसका उपयोग डिटर्जेंट, सिलिकेट, अल्ट्रामरीन, बाइक्रोमेट आदि के निर्माण में भी हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोडा ऐश के दोनों ग्रेड, कई सामान्य उपयोगों के कारण, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं। प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि लाइट और डेंस सोडा ऐश में अंतर केवल बल्क घनत्व में है, किंतु उत्पाद की विशेषताएँ, उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण तकनीक, कच्ची सामग्री, मानवशक्ति, कार्य और उपयोग, सीमा शुल्क वर्गीकरण और लाइट और डेंस सोडा ऐश की कीमत एक समान हैं, तथापि डेंस सोडा ऐश के निर्माण के लिए अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना आवश्यक है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि तथापि कुछ अंतिम अनुप्रयोगों में विशेष रूप से लाइट या डेंस सोडा ऐश की आवश्यकता हो सकती है, बल्क घनत्व या कुछ उपभोक्ताओं द्वारा लाइट और डेंस सोडा ऐश का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने में असमर्थता, दोनों को असमान वस्तुएँ नहीं बना सकतीं। ये एक ही उत्पाद के दो अलग-अलग रूप मात्र हैं।

20. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार निर्धारित करते हैं:

“विचाराधीन उत्पाद "डिसोडियम कार्बोनेट" है, जिसे "सोडा ऐश" के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा ऐश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील पदार्थ है। भारतीय उत्पादकों द्वारा इसका उत्पादन दो रूपों में किया जाता है - लाइट सोडा ऐश और डेंस सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर उनके बल्क घनत्व का है। यह प्राकृतिक सोडा ऐश या सिंथेटिक सोडा ऐश हो सकता है। दोनों उत्पाद मूलतः एक जैसे हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत, कोड 283620 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं। प्राधिकारी यह मानता हैं कि आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

ङ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

ङ 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. दो घरेलू उत्पादक, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और निरमा लिमिटेड, घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र हैं क्योंकि वे संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित हैं।

ii. टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड, दोनों के अमेरिका में संबंधित निर्यातक हैं। चूँकि उनके संबंधित उत्पादक हैं, इसलिए वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र नहीं हैं।

ङ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान जाँच के लिए आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एएमएआई देश में संबंधित उत्पाद के घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल, टीसीएल और जीएचसीएल जैसे भागीदार उत्पादक शामिल हैं। संबंधित उत्पाद का एक अन्य उत्पादक तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) भी है।

ii. आवेदक कंपनियाँ कुल भारतीय घरेलू उत्पादन का 98% हिस्सा बनाती हैं। आवेदक कंपनियाँ डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, आरएसपीएल लिमिटेड और जीएचसीएल लिमिटेड ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।

iii. टाटा केमिकल्स का अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है, किंतु उसने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। अमेरिका में इस संबंधित कंपनी ने आधार वर्ष में ही मामूली मात्रा में निर्यात किया है।

iv. निरमा लिमिटेड का अमेरिका में एक संबंधित उत्पादक है। अमेरिका में निरमा लिमिटेड के संबंधित उत्पादक ने जांच की अवधि में अंतिम उपभोक्ता को बहुत कम निर्यात किया है। निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्षकार, सियरलेस वैली मिनरल्स ("एसवीएम") द्वारा किए गए निर्यात निरमा के उत्पादन और बिक्री तथा भारत में कुल आयात के संबंध में नगण्य हैं। प्राधिकारी के पास सूचना पहले से ही रिकॉर्ड में है। इन निर्यातों का निरमा लिमिटेड से कोई लेना-देना नहीं है और यदि एडीडी लगाया जाता है, तो वह इन निर्यातकों पर भी समान रूप से लागू होगा।

v. इस प्रकार, आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग का गठन करती हैं।

vi. घरेलू उद्योग ने जांच शुरू होने से पहले, 26 सितंबर 2024 को अलग से पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि निरमा के संबंधित पक्षकार ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह पत्र एनसीवी आवेदन में परिशिष्ट के रूप में भी संलग्न किया गया था।

vii. घरेलू उद्योग के दावे और प्राधिकारी द्वारा आरंभिक अधिसूचना में दिए गए निष्कर्षों में एकरूपता है। आयात संबद्ध पक्ष (एसवीएम) द्वारा संबद्ध देश में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष को किए गए हैं।

viii. निरमा के उत्पादन, बिक्री और कुल आयात के संबंध में एसवीएम का कुल निर्यात नगण्य है। ये आयात एक स्वतंत्र क्रेता को किए गए थे, निरमा द्वारा नहीं।

ix. टाटा केमिकल्स के संबद्ध पक्षकार ने आधार वर्ष में केवल नाममात्र का निर्यात किया और जांच अवधि में कोई आयात नहीं दर्शाया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

"(ख) *''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।''*

25. वर्तमान आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले उत्पादक डीसीडब्ल्यू, आरएसपीएल, निरमा लिमिटेड, टीसीएल और जीएचसीएल हैं। तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएसी) नामक एक अन्य उत्पादक भी है। जाँच अवधि में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित निर्यातक है। आवेदकों ने इस संबंध में अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में टाटा केमिकल्स लिमिटेड के संबंधित उत्पादक से कोई निर्यात नहीं हुआ है और आधार वर्ष में केवल नगण्य मात्रा में निर्यात किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि निरमा लिमिटेड का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित निर्यातक है। इस संबंध में आवेदकों ने अनुरोध किया है कि निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष, सियरलेस वैली मिनरल्स ("एसवीएम") का जांच की अवधि में न्यूनतम निर्यात है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार के निर्यात

संबंधित पक्ष द्वारा सीधे अंतिम ग्राहक को किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में एसवीएम से आयात निरमा लिमिटेड के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ भारत में कुल आयात के संबंध में नगण्य और महत्वहीन है। नीचे दी गई तालिका टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड की संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए निर्यात का विवरण प्रदान करती है:

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23**	**अक्तू.23-जून 24 (पीओआई)**
टाटा की संबंधित पार्टी द्वारा भारत में निर्यात	एमटी	***	शून्य	शून्य	शून्य
टाटा के उत्पादन के संबंध में	% श्रेणी	0-1	-	-	-
कुल आयात के संबंध में	% श्रेणी	0-1	-	-	-

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23**	**अक्तू.23-जून 24 (पीओआई)**
निरमा की संबंधित पक्षकार द्वारा भारत में निर्यात	एमटी	***	***	***	***

निरमा के उत्पादन के संबंध में	% श्रेणी	2-3	0-1	0-1	0-1%
कुल आयात के संबंध में	% श्रेणी	3-4	0-1	2-3	0-1

27. निर्यात की मात्रा, भारत में कंपनियों द्वारा उत्पादन की मात्रा और कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि कंपनियों का ध्यान भारत में उत्पादन पर है, न कि आयात पर। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूँकि आयात नगण्य हैं, इसलिए यह निरमा लिमिटेड और टाटा केमिकल्स की पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग माने जाने की पात्रता को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शेष आवेदक कंपनियों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।

28. हितबद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि टाटा केमिकल्स, तूतीकोरिन, अमेरिका के निर्यातक से संबंधित है और बदले में तूतीकोरिन, भारत से संबंधित है, यह देखा गया है कि इस दावे को साक्ष्यों से पुष्ट नहीं किया गया है और न ही लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे घरेलू उद्योग पर्याप्त रूप से उत्तर दे सके।

29. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और उपर्युक्त जांचे गए मुद्दों के मद्देनजर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक कंपनियाँ पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार, यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

च. <u>गोपनीयता</u>

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्ता ने सौदा-वार आयात आँकड़े उसी प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराए हैं जिस प्रारूप में मूल रूप से दर्ज किए गए थे। आँकड़ों की यह कमी (और गोपनीयता के दावों पर अत्यधिक निर्भरता) सार्थक विश्लेषण में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालती है। याचिकाकर्ता के गोपनीयता के अनेक दावे (उत्पादन आँकड़े, लागत घटक, बिक्री आँकड़े, आदि सहित) अत्यधिक हैं और स्थापित व्यापार सूचना दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। उचित और सुदृढ़ समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी को अगोपनीय तरीके से प्रकट किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना का पालन नहीं किया है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

iii. व्यापार सूचना 10/2018, 2/2000, 2/2004 का उल्लंघन हुआ है। 2 से अधिक कंपनियों के मामले में सूचना को गोपनीय बताया गया है।

iv. प्राधिकारी ने एक ऐसे आवेदन को स्वीकार करके व्यापार नोटिस से अलग व्यवहार किया है जो गोपनीय अनुरोध रिकॉर्ड में लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित अनिवार्य पूर्व शर्तों के अनुरूप नहीं है। बाजार रिपोर्ट जैसी सूचनाओं को गोपनीय बताया गया है।

v. 28 अगस्त 2000 की व्यापार नोटिस संख्या 2/2000 में पाटनरोधी जाँचों में गोपनीयता का दावा करने के लिए अपनाई जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का प्रावधान है और आवेदक द्वारा 9 महीने की जाँच अवधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत अद्यतन आंकड़ों के संबंध में ऐसी आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध की किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने डीजीटीआर व्यापार सूचना के अंतर्गत निर्धारित गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन किया है। अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों में विस्तृत सारांश, गोपनीय आंकड़ों का सूचीकरण और गोपनीयता के दावों के लिए पर्याप्त तर्क शामिल हैं।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो पारदर्शिता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं और इस प्रकार उचित खंडन और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विरोधी पक्षकारों को व्यापार सूचना का समान रूप से अनुपालन करने और अपर्याप्त रूप से प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने का निर्देश दें।

iii. संबद्ध वस्तुओं का एक समर्पित कोड है, इसलिए आवेदन डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, न कि डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों या द्वितीयक स्रोत से प्राप्त सौदे-वार आंकड़ों के आधार पर।

iv. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निर्धारित दिशानिर्देश संवेदनशील जानकारी को गोपनीय आधार पर संरक्षित करने की अनुमति देते हैं। घरेलू उद्योग ने जहाँ उपयुक्त हो, आवश्यक सारांश और संपादित आँकड़े उपलब्ध कराकर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

v. घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षति मापदंडों, सूचनाओं, साक्ष्यों और विभिन्न क्षति मापदंडों के निर्धारण से संबंधित या संगत दस्तावेजों, अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री मात्रा जैसी सूचनाओं की गोपनीयता का दावा इस आधार पर किया है कि ये व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचनाएँ हैं, उनके प्रकटीकरण से किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा या घरेलू उद्योग के वास्तविक व्यावसायिक हितों के लिए

हानिकारक होगा। इसलिए, ऐसी सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किए जा सकते।

vi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध मापदंडों के लिए वास्तविक जानकारी के प्रकटन से तत्काल जाँच में घरेलू उद्योग के गोपनीय आँकड़े प्रकट हो जाएँगे।

vii. हितबद्ध पक्षकार ने 03 मार्च, 2025 के पत्राचार का उल्लेख किया है। उक्त पत्राचार घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी अनुरोध को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए।

viii. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि हितबद्ध पक्षकार विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अंधेरे में न रखें और उनकी जानकारी के बिना कोई कार्रवाई न करें और इसलिए हितबद्ध पक्षकार की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण थी।

ix. प्राधिकारी ने उत्तर मांगते हुए घरेलू उद्योग के साथ अनुरोध साझा किया और घरेलू उद्योग ने 7 मार्च 2025 की ईमेल के माध्यम से उत्तर दिया था और अनुरोध की स्वीकृति पर आपत्ति जताई थी क्योंकि यह जांच शुरू करने के नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद की गई थी।

x. हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोधों में 60 दिनों से अधिक की देरी हुई थी, क्योंकि अनुरोध 3 मार्च 2025 को किया गया था, जबकि जांच की शुरूआत 29 सितंबर 2024 को हुई थी। विलंबित अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, या, यदि आवश्यक हो तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाना चाहिए कि अनुरोध में इतनी देरी क्यों हुई।

xi. घरेलू उद्योग के गोपनीयता दावों की ओर इशारा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को सात दिन का समय दिया गया था। प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए दावे स्पष्ट रूप से समय सीमा पार कर चुके हैं।

xii. आवेदन में सूचना की गोपनीयता का दावा करने का कारण दिया गया था। प्रस्तुत की गई अद्यतन सूचना में जांच की अवधि में परिवर्तन के कारण उसी सूचना का अद्यतनीकरण शामिल था और इस प्रकार ऐसी सूचना के लिए दावा करने का तर्क वही रहेगा, जैसा कि समान सूचना प्रदान करने वाले आवेदन में तर्क दिया गया था। गोपनीयता के पहलू से सूचना या अनुरोध केवल अद्यतनीकरण था। आवेदन में दिए गए गोपनीयता तर्क को अद्यतन सूचना के लिए भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

xiii. प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने प्रत्युत्तरों के सार्वजनिक अंश में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसमें शेयरधारकों के नाम, कंपनी और संबद्ध कंपनियों का विवरण, शेयरधारिता प्रतिशत, कंपनी, संबद्ध कंपनियों का विवरण और साथ ही संबंधित कंपनियों की गतिविधियों जैसी सूचनाओं को गोपनीय बताया गया है।

xiv. नमूना घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेज़ों का खुलासा नहीं किया गया है। तथापि दस्तावेज़ स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, प्रस्तुत दस्तावेज़ों की सूची का खुलासा नहीं किया गया है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

32. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जाँच के

दौरान किसी भी पक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर, उसने द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्ष को ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के योग्य नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी इसका विवरण देगा कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों का विरोध करते हुए, घरेलू उद्योग ने फिर भी क्षति सूचना का एक संशोधित अगोपनीय अंश प्रकट किया है, जिसमें सूचना का प्रकटीकरण पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस अनुरोध के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने अक्टूबर 2023-मार्च 2024 के साथ-साथ अक्टूबर 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए संशोधित क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि गोपनीयता संबंधी चिंताएँ जताने वाले हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा के काफी बाद, विलंबित अनुरोध किया। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने 13 मई 2025 को संशोधित सूचना प्रदान की और परिचालित की, जिसमें उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, कर्मचारी, प्रतिदिन उत्पादकता और मालसूची जैसे मानदंडों की वास्तविक जानकारी शामिल है।

35. प्राधिकारी, जहाँ भी दावा किया गया हो, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, ग्राहक का नाम, बिक्री/खरीद बीजक, और इस सूचना के समर्थन में या इस सूचना से संबंधित दस्तावेज़/सूचना जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों को अनुमति करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी, जहाँ भी दावा किया गया हो, निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न निष्पादन संकेतकों, बिक्री मात्रा और कीमत, कीमत समायोजन और इनके समर्थन में या इनके संबंध में प्रदान की गई विभिन्न सूचनाओं और दस्तावेज़ों जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता के दावों को अनुमति करते हैं। प्राधिकारी का मानना है कि यह सूचना स्वभाविक रुप से गोपनीय है और वास्तविक आधार पर इन सूचनाओं और दस्तावेज़ों का खुलासा संबंधित पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और प्रतिस्पर्धियों और विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है और इसे उचित माना गया है।

छ. <u>विविध मुद्दे</u>

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्ता ने छह महीने की जाँच अवधि का प्रस्ताव किया था, किंतु प्राधिकारी ने नौ महीने की अवधि स्वीकार कर ली है। दोनों अवधियाँ व्यापक विश्लेषण करने के लिए बहुत कम हैं और 12 महीने के मानक (जैसा कि नियमावली के अंतर्गत निर्धारित है) से किसी भी विचलन को स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जाना चाहिए।

ii. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के कम अवधि की जांच अवधि के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने में निर्धारित अवधि पर स्पष्ट रूप से टिप्पणियां भी आमंत्रित नहीं की हैं।

iii. वर्तमान जांच प्रारंभिक जॉच परिणाम जारी करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

iv. पूर्वव्यापी आधार पर एडीडी की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य का अभाव है। पूर्वव्यापी शुल्क लगाने की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

v. याचिकाकर्ता व्यापार उपचारों के आदतन प्रयोक्ता हैं। इस विषय-वस्तु में पिछले मामलों का संदर्भ दिया गया है। इसे अब तक पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो चुका है।

vi. प्राधिकारी ने इस मामले में उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित समय नहीं दिया है, जबकि आवेदकों ने 31.12.2024 को संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया था और अनुरोध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4.01.2025 निर्धारित की गई थी।

vii. आवेदकों द्वारा डीसीपीसी और डीजीटीआर के समक्ष विरोधाभासी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

viii. उद्योग को पहले ही एमआईपी लगाकर सुरक्षा मिल चुकी है और एडीडी लगाना अनुचित है। इसके अलावा, सोडा ऐश के लिए न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) की मौजूदगी को किसी भी संभावित खतरे को कम कर देना चाहिए।

ix. क्षति अवधि की जानकारी भी व्यापार सूचनाओं के विपरीत है - 2020-2021 (12 महीने- वित्तीय वर्ष), 2021-2022 (12 महीने वित्तीय वर्ष), अप्रैल 2022-सितंबर 2023 (15 महीने- वित्तीय वर्ष नहीं) और पीओआई (अक्टूबर 2023-जून 2024-9 महीने) के लिए

जानकारी प्रदान की गई है। प्रतिवादी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर अपनी टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं है।

x. यह कार्यवाही एडी करार के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन है। डीआई की पूरी जानकारी जॉच शुरुआत के 3 महीने बाद दिसंबर में ही प्रदान की गई थी।

xi. विस्तारित जांच अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन/वचनबद्धता का अभाव है। जांच की शुरूआत के समय जांच अवधि के आंकड़ों के अभाव से यह सुनिश्चित हुआ कि नियम 5 में उल्लिखित पूर्व-शर्तों का पालन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर रही है। प्रस्तुत किए गए अद्यतन आंकड़ों में कोई प्रमाणन/वचनबद्धता नहीं है।

xii. इस कार्यवाही में नियम 6 के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नियम 6(1)(ii) के साथ पठित नियम 6(1)(i), प्राधिकारी पर जांच की शुरूआत करने के अपने निर्णय को अधिसूचित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का कानूनी दायित्व डालता है। ऐसी सार्वजनिक सूचना में आवेदन में जिस आधार पर पाटन का आरोप लगाया गया है, उसके संबंध में पर्याप्त जानकारी और उन कारकों का सारांश शामिल होना आवश्यक है जिन पर क्षति का आरोप आधारित है। वर्तमान मामले में, चूंकि जांच की पूरी अवधि से संबंधित आंकड़ों वाला कोई भी आवेदन जांच की शुरूआत करते समय प्राधिकारी के समक्ष नहीं था, इसलिए जांच शुरूआत अधिसूचना निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। नियम 6(1)(vi) के अनुसार, प्राधिकारी को जाँच में अपनाई जाने वाली समय-सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। पूर्ण आवेदन के अभाव में यह सुनिश्चित हो गया कि जाँच आरंभ अधिसूचना में अधिसूचित समय-सीमाएँ अनावश्यक थीं।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

38. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. इस जाँच की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए 9 महीने की जाँच अवधि उचित है। प्राधिकारी द्वारा 9 महीने की जाँच अवधि का चयन, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जाँच अवधि पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप है। नियम 5 (3क) न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 18 महीने की अवधि का प्रावधान करता है। तथापि याचिका 6 महीने की अवधि के लिए प्रस्तुत की गई थी, प्राधिकारी ने इसे पहले ही एक तिमाही के लिए बढ़ा दिया है और इसे नौ महीने की जाँच अवधि बना दिया है।

ii. प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जाँच अवधि, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सही स्थिति प्रस्तुत करती है।

iii. जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही में दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। भारतीय सीमा शुल्क विभाग में दर्ज सीआईएफ आयात कीमत बहुत अधिक है (जो निर्यात और आयात के बीच समय अंतराल के कारण हो सकता है)। चूँकि डीजीटीआर, सीआईएफ आयात कीमत का उपयोग करके क्षति मार्जिन निर्धारित करता है, इसलिए जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही को शामिल करना अनुचित होता और इससे क्षति मार्जिन विकृत हो जाता।

iv. घरेलू उद्योग समझता है कि प्राधिकारी अब अंतिम जाँच परिणाम के लिए मामले पर विचार और प्रक्रिया कर रहे हैं। इसलिए यह मुद्दा अब संगत नहीं है। पूर्वव्यापी प्रभाव से एडीडी लगाने के अनुरोधों के संबंध में, पहले किए गए सभी अनुरोध दोहराये जाते हैं।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए दावे त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हैं। घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में प्रमाणित और संबोधित किया है कि शुल्क प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के बाद लगाए गए हैं कि पाटन से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के इस दावे के बावजूद कि क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, शुल्कों को समाप्त होने दिया गया। बार-बार पाटन से बार-बार होने वाली क्षति, उपायों की आवश्यकता को प्रमाणित करती है न कि उनकी वैधता को कम करती है।

vi. हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त और अनेक अवसर मिले हैं।

vii. डीसीपीसी और डीजीटीआर के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का प्रमाण देती है। प्रवृत्ति विश्लेषण डीसीपीसी के साथ-साथ डीजीटीआर के समक्ष भी यही स्थिति दिखाता है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि में 2024-25 की पहली तिमाही शामिल है, जबकि डीसीपीसी की जानकारी से तुलना उस अवधि से संबंधित है जिसमें 2024-24 की पहली तिमाही शामिल नहीं है। तथापि, दोनों क्षति सूचनाओं में प्रवृत्ति समान बनी हुई है जो दर्शाती है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति से ग्रस्त है।

viii. आयात आंकड़ों (जांच की अवधि, जांच की अवधि के बाद और जांच की शुरुआत के बाद) से प्रमाणित पाटित आयातों में तेजी से वृद्धि स्पष्ट रूप से एक ऐसे खतरे की ओर इशारा करती है जो अनियंत्रित रहने पर और बढ़ जाएगा। एमआईपी का अस्तित्व अनुचित कीमत वाले आयातों द्वारा लगाए गए प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान को पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं करता है। इसके अलावा, एमआईपी का अधिरोपण केवल 30 दिसंबर 2024 से 30 जून 2025 तक 6 महीने की अवधि के लिए किया गया है। लागू की गई एमआईपी 20,108 रुपये प्रति मीट्रिक टन है जो अभी भी घरेलू उद्योग की एनआईपी से काफी कम है।

ix. यह नहीं माना जा सकता कि एमआईपी के लागू होने से घरेलू उद्योग की परेशानियों का समाधान हो गया है। एमआईपी का अधिरोपण व्यापार सुधारात्मक उपायों का विकल्प नहीं है। एमआईपी के अधिरोपण के बावजूद, आयात देश में पाटित किए जा रहे हैं।

x. जहां तक व्यापार सूचना 2/2004 का संबंध है, उक्त सूचना को व्यापार सूचना संख्या 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर 2013 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उक्त व्यापार सूचना की एक प्रति संलग्न है। चूंकि व्यापार सूचना स्वयं प्रतिस्थापित है, इसलिए किसी भी तरह से इसका संदर्भ गलत है। वर्तमान मामले में प्रस्तुत तरीके से क्षति अवधि की अनुमति देना प्राधिकारी की वर्तमान प्रथा है। पिछले वर्ष केवल तभी वित्तीय वर्ष होते हैं जब जांच की अवधि अप्रैल से शुरू होती है। यदि जांच की अवधि अप्रैल से शुरू नहीं होती है, तो पूर्ववर्ती अवधि अनिवार्य रूप से जांच की अवधि से पहले वाले महीने के साथ समाप्त होनी चाहिए। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस कारण

से किसी पूर्वाग्रह का दावा नहीं किया जा सकता है। यदि आकड़ों को 2022-23 और अप्रैल-सितंबर, 2023 के लिए अलग-अलग लिया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि यह समान प्रवृत्ति स्थापित करेंगे।

xi. यह आरोप कि वर्तमान कार्यवाही पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन करती है, गलत है क्योंकि हितबद्ध पक्षकार द्वारा पहली बार 03 मार्च 2025 को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार के पास अद्यतन आंकड़ों के साथ आवेदन पर टिप्पणी करने के लिए 61 दिनों का समय था।

xii. विस्तारित जांच अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन या वचनबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन में ये आवश्यकताएं केवल इसलिए हैं क्योंकि प्राधिकारी को आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करनी है और स्वयं को संतुष्ट करना है कि जहां लागू हो, वहां पाटन, क्षति, और जहां लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करते हैं।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों को दी गई समय-सीमा निम्नलिखित के संबंध में थी - प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई जानकारी प्रदान करना तथा आवेदन में निहित जानकारी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना। टिप्पणियों के लिए ऐसा अवसर अद्यतन अवधि के आंकड़ों के संबंध में नहीं था। उक्त अवसर नियम 6(7) के अंतर्गत हितबद्ध पक्ष को उपलब्ध हुआ। ऐसा ही किया गया है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:

क. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध वस्तुओं पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) लागू है, यह नोट किया जाता है कि यह उपाय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत व्यापार उपाय का विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिस स्तर पर एमआईपी

निर्धारित किया गया है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति-रहित कीमत पर विचार करने पर, यह देखा गया है कि डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एमआईपी, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति-रहित कीमत से काफी कम है। इस प्रकार, यदि आयात एमआईपी पर होता है, तो भी इससे भारतीय उद्योग को क्षति होगी। इस प्रकार, एमआईपी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान नहीं करेगा।

ख. इस तर्क के संबंध में कि 9 महीने की जांच अवधि उपयुक्त नहीं है और इस पर विचार करने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 12 महीने से कम की जांच अवधि अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान मामले में, जबकि घरेलू उद्योग ने 6 महीने की जांच अवधि का प्रस्ताव रखा था, प्राधिकारी ने उचित विचार-विमर्श के बाद इसे जाँच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं पाया। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि 9 महीने की जांच अवधि अधिक उपयुक्त होगी और ऐसा निर्धारण पाटनरोधी जांचों को नियंत्रित करने वाली नियमावली के दायरे में आता है। नियमावली के नियम 5(3क) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"5(3क) जांच की अवधि, -

(i) जांच की शुरूआत की तारीख से छह महीने से अधिक पहले की नहीं होगी;

(ii) सामान्यतः बारह महीने की अवधि होगी और लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने वाले के साथ, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।"

यह नोट किया जाता है कि नियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि जांच की अवधि (पीओआई) न्यूनतम छह महीने की होगी और अठारह महीने तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे निर्धारण के कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

इस तर्क के संबंध में कि क्षति संबंधी जानकारी 12 मई 2004 की व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के विपरीत है, प्राधिकारी निम्नलिखित टिप्पणी करते हैं:

i. उस समय, जांच की शुरुआत में, घरेलू उद्योग के उन तर्कों पर उचित ध्यान दिया गया था, जिनमें यह तर्क दिया गया था कि सितंबर 2023 से पहले की अवधि को जांच की अवधि का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात कीमतों में उक्त गिरावट के साथ-साथ बिक्री लागत में भी आनुपातिक गिरावट नहीं आई है। तदनुसार, जुलाई 2023 से सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग पर पाटन के हानिकारक प्रभाव का सही-सही पता नहीं चलेगा।

क्र.सं.	देश	संबद्ध देशों से कीमत (रु./एमटी)
1	जनवरी 2023	32,539
2	फरवरी 2023	33,572
3	मार्च 2023	31,036
4	अप्रैल 2023	30,663
5	मई 2023	29,969
6	जून 2023	29,522
7	जुलाई 2023	27,051
8	अगस्त 2023	26,052
9	सित. 2023	21,887
10	**2023-24एच1**	**27,327**

11	अक्तू. 2023	20,175
12	नव. 2023	20,679
13	दिस. 2023	19,973
14	जनवरी 2024	19,267
15	फरवरी 2024	19,907
16	मार्च 2024	18,543
17	**2023-24एच2**	**19,756**
18	अप्रैल 2024	18,520
19	मई 2024	19,066
20	जून 2024	18,332
21	**2024-25क्यू1**	**18,693**

ii. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी को बारह महीनों के अलावा अन्य अवधि अपनाने के लिए कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि ऐसे कारणों को जांच प्रारंभ की सूचना में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि जांच प्रारंभ की सूचना में बारह महीनों से कम या अधिक अवधि अपनाने के कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्राधिकारी का मानना है कि यह पर्याप्त है कि अंतिम निर्धारण में कारणों को स्पष्ट कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में कारण बताए हैं और हितबद्ध पक्षकारों को उनकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर मिला है।

iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवधियों में पूर्ण वित्तीय वर्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि बिना किसी अंतराल के एक सतत अवधि है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि से पहले के वर्ष को केवल तभी पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जा

सकता है, जब जांच की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जांच की अवधि से पूर्व वर्ष में एक वित्तीय वर्ष और 6 महीने, अर्थात् 22 अप्रैल - 23 सितंबर, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा पिछले कई मामलों में लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वर्तमान जाँच, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.1.3 का उल्लंघन है क्योंकि घरेलू उद्योग की पूरी जानकारी जाँच शुरू होने के केवल 3 महीने बाद ही प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 6.1.3 में निम्नलिखित उल्लेख है:

जांच शुरू होते ही, प्राधिकारी अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्राप्त लिखित आवेदन का पूरा पाठ ज्ञात निर्यातकों और निर्यातक सदस्य के प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएँगे और अनुरोध किए जाने पर, इसे अन्य संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएँगे। अनुच्छेद 5 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

प्राधिकारी ने, जाँच की शुरूआत के समय, अनुच्छेद 6.1.3 के अनुसरण में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन का पूरा पाठ परिचालित किया। इस प्रकार, जांच शुरू करने के उद्देश्य से विचार किए गए आवेदन को जांच शुरू करने के चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 और भारतीय नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत आवश्यकता पूरी होती है। इसके अलावा, जांच अवधि को एक तिमाही तक बढ़ाने के प्राधिकारी के निर्णय के बाद, घरेलू उद्योग को सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई समयावधि के भीतर विस्तारित अवधि के लिए अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। ये आकड़े बाद में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए थे और संबंधित अगोपनीय अंश 31 दिसंबर 2024 को हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। यह देखा गया है कि हितबद्ध पक्षकार ने 31 दिसंबर 2024 को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित अगोपीय अंश पर टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और की गई टिप्पणियों

पर वर्तमान निर्धारण में विचार किया गया है, जो दर्शाता है कि पक्षकारों को जवाब देने और कोई भी टिप्पणी प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक समय प्रदान किया गया था।

घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग एक आदतन व्यापार उपचार प्रयोक्ता है, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की पाटन का इतिहास रहा है। सभी पूर्ववर्ती जाँचों में विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन की मौजूदगी का पता चला है। इस प्रकार यह देखा गया है कि विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद की पाटन का सहारा लेते रहे हैं। किसी भी भागीदार उत्पादक ने न तो कोई अनुरोध किया है और न ही इस बारे में कोई जानकारी दी है कि उत्पाद को इतनी बार पाटन कीमत पर निर्यात क्यों किया गया है। यह सर्वविदित है कि भारत एक कीमत-संवेदनशील बाजार है और वर्तमान जाँच में संबद्ध देशों सहित अन्य देशों के उत्पादकों ने आदतन भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की पाटन का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जाँच से पहले लगाए गए कोई भी उपाय, की गई जाँच के आधार पर और यह स्थापित होने के बाद लगाए गए उचित उपाय हैं कि कानून के अंतर्गत आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं। वर्तमान जाँच, पूर्व की जाँचों और लगाए गए उपायों से भिन्न तथ्यों के आधार पर एक नई जाँच है। यदि वर्तमान जाँच में शुल्कों की सिफारिश की जानी है, तो वह पूरी और गहन जाँच के बाद ही की जाएगी। अमेरिका और तुर्की के प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों ने पाटन की बात स्वीकार की है। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से भी यह बात साबित होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निर्यातकों ने स्वयं पाटन की बात स्वीकार की है।

ज. <u>पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने देश-विशिष्ट बाजार स्थितियों के लिए पर्याप्त समायोजन किए बिना भारतीय उत्पादन लागत के आधार पर ईरान, तुर्की और रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

ii. आईएचएस मार्किट: सोडा ऐश मंथली के तृतीय पक्ष के आकड़ों पर निर्भरता अमेरिका में वास्तविक बाजार कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

iii. घरेलू उद्योग ने केवल यह दावा किया है कि उसे रूस में घरेलू बिक्री कीमतों का कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसलिए उसने परिकलित सामान्य मूल्य का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

iv. घरेलू उद्योग के आवेदन में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन इस दृष्टिकोण से किया गया था कि इसे यथासंभव सही बनाया जा सके।

v. आवेदकों द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन का आकलन किया जाना चाहिए।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. घरेलू उद्योग ईरान में उत्पाद की कीमतों के साक्ष्य एकत्र करने में असमर्थ रहा क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को उचित रूप से जोड़ने के बाद, ईरान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ii. घरेलू उद्योग, अमेरिकी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक सौदा कीमतों के रूप में कीमत की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। घरेलू उद्योग ने अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु, जांच अवधि के लिए एचआईएस मार्किट: ग्लोबल सोडा ऐश मंथली के रूप में प्रकाशित कीमतों पर विचार किया है।

iii. घरेलू उद्योग, तुर्की के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को उचित जोड़कर, तुर्की के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

iv. घरेलू उद्योग, रूस के घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की जानकारी एकत्र करने में असमर्थ रहा। इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को उचित जोड़कर, रूस के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया। प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए:

क. सीमित देयता कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री", रूस
ख. संयुक्त स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी, रूस
ग. संयुक्त स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फ़ैक्टरी, रूस
घ. डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., तुर्की
ड़. पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी, यूएई
च. पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी, यूएई
छ. टुट्टी डीडसीसी, यूएई
ज. एडीवी इंटरनेशनल, यूएई
झ. एजी सिनेर इथालट, तुर्की
ञ. ईटीआई सोडा यूरेटिम पज़ारलामा, तुर्की
ट. कज़ान सोडा एल्ट्रिक, तुर्की
ठ. सोडा वर्ल्ड, यूके

ड. यूजी इम्पेक्स जेनरेट ट्रेडिंग, यूएई
ढ. यूनीवर्ल्ड ग्लोबल, यूएई
ण. डब्ल्यूई आईसी वी डीआईएस टिकारेट, तुर्की
त. सिसेकैम डीआईएस टिकारेट, तुर्की
थ. तुर्किये सिसे वी कैम फ़ैब्रिकलारी, तुर्की
द. हिरण्यवर्णम केमिकल्स, सिंगापुर
ध. केम्पार एनर्जी, सिंगापुर
न. सिसेकैम व्योमिंग, यूएसए

44. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

<u>**तुर्की**</u>

क्र.सं.	**उत्पादक/देश**	**निर्यातक/देश**
1	तुर्किये सिसअम कैम फेब्रिकलान ए एस, तुर्की	1. सिसेकेम दिस टिकारेत ए एस (एसडीटी), तुर्की 2. यूनिवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ, यूएई
2	कजान सोड इनलेक्ट्रिक यूतमजपउ ए एस, तुर्की	1. वी आईसी वे दिस टिकारेट ए एस, तुर्की 2. सोडा वर्ल्ड, यूके
3	ईटीआई सोडा यूरेटिमपजारलामानकलीयत वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे टिकारेत एएस, तुर्की	1. ईटीआई सोडा यूरेटिम पजारलामा नाकलियात वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सानायी वे टिकारेट ए एस तुर्की 3. वी आईसी वे दिस टिकारेट ए एस, तुर्की 2. सोडा वर्ल्ड, यूके 3. एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ, यूएई 4. यू जी इम्पैक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसीए यूएई 5. यूनिवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ, यूएई

<u>**क. सामान्य मूल्य का निर्धारण**</u>

i. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी ए एस (सिसेकैम समूह)

45. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी ए एस ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

46. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ii. मेसर्स कज़ान सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस. (डब्ल्यूई सोडा लिमिटेड)

47. मेसर्स कज़ान सोडा ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभ कमाने वाली घरेलू

बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

48. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

iii. मेसर्स ईटीआई सोडा यूरेटिमपज़ारलामानाक्लीयत वे इलेक्ट्रिकयूरेटिम सनाय वे टिकारेट ए.एस. (उत्पादक/निर्यातक, तुर्की) (डब्ल्यूई सोडा लिमिटेड)

49. मेसर्स ईटीआई सोडा ने जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

50. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

51. मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स तुर्की सिसे वे कैम फ़ैब्रिकलरी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को असंबंधित निर्यातक मेसर्स सिसेकैम डिस टिकारेट के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।

52. मेसर्स कज़ान सोडा द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स कज़ान सोडा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सोडा वर्ल्ड लिमिटेड के माध्यम से *** मीट्रिक टन, एडीवी इंटरनेशनल एफज़ेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन और यूजी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।

53. मेसर्स ईटीआई सोडा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में, यह देखा गया है कि मेसर्स ईटीआई सोडा संबंधित वस्तुओं का उत्पादक है। इसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन निर्यात किया है और सोडा वर्ल्ड लिमिटेड के माध्यम से *** मीट्रिक टन, एडीवी इंटरनेशनल एफजेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन, यूजी इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन और यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।

54. उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को वस्तु बेची है। निर्यात कीमत को कारखाना-

द्वार कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया था। चूँकि कई निर्यात चैनल हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

रूस

क्र.सं.	उत्पादक/देश	निर्यातक/देश
1	**मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी (निर्माता/निर्यातक, रूस)**	**i. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फ़ैक्टरी (निर्यातक, रूस)** **ii. मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री" (निर्यातक/व्यापारी, रूस)** **iii. मेसर्स डीएमसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस. (निर्यातक/व्यापारी, तुर्की)** **iv. मेसर्स पैसिफिक वाटर्स डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात)** **v. मेसर्स पोंटस ट्रेडिंग डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात)** **vi. मेसर्स टुट्टी डीएमसीसी (निर्यातक/व्यापारी, संयुक्त अरब अमीरात)**

क. सामान्य मूल्य का निर्धारण

मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी (उत्पादक/निर्यातक, रूस)

55. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी, मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री, मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री", मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., मेसर्स पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी, मेसर्स पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी, और मेसर्स टुट्टी डीडसीसी संबंधित पक्ष हैं। मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी और मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री रूस में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं। उपर्युक्त सभी पक्षकारों ने निर्धारित निर्यातक

प्रश्नावली प्रारूप में संगत जानकारी प्रदान की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभप्रद सौदा 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए लेन-देनों पर विचार किया है और यदि लाभप्रद सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से कम बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए लाभप्रद बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

56. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ख. निर्यात कीमत का निर्धारण

57. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी, मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री, मेसर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ट्रेड हाउस "बश्किरियन केमिस्ट्री", मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस., मेसर्स पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी, मेसर्स पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी और मेसर्स टूटी डीडसीसी संबंधित पक्ष हैं। यह नोट किया जाता है कि मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी ने भारत को कुल *** मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें मेसर्स डीडसी डेल्टा डैनिस्मैनलिक वे टिकारेट ए.एस. के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया गया है, जिसमें से मेसर्स पोंटस ट्रेडिंग डीडसीसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन और मेसर्स टूटी डीडसीसी के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया

गया है। इसने मेसर्स पैसिफिक वाटर्स डीडसीसी के माध्यम से भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन निर्यात किया है।

58. मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी और मेसर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन का दावा किया है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को बेचा है। निर्यात कीमत को कारखाना-बाहरी कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया। चूँकि निर्यात के कई माध्यम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>यूएसए</u>

क्र.सं.	**उत्पादक/ देश**	**निर्यातक/देश**
1	**मैं. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी**	i. **मैं हिरण्यवर्मनाम कैमिकल्स** ii. **मै. कैम्पर एनर्जी** iii. **मै. लिब्रा अल्कलीस्कीमी(आयातक)**

<u>क. सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी

59. मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी, अमेरिका में विषयगत वस्तुओं का उत्पादक है। मेसर्स हिरण्यवर्णम केमिकल्स और मेसर्स केम्पार एनर्जी ने मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया है। मेसर्स लिब्रा अल्कालिस्केमी एक असंबंधित आयातक है जिसने उपर्युक्त पक्षों से विषयगत वस्तुओं का आयात किया है। उपर्युक्त सभी पक्षकारों ने निर्धारित प्रश्नावली प्रारूप में संगत जानकारी प्रदान की है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादन लागत और एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। जहाँ लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, वहाँ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में हुए सौदे पर विचार किया और यदि लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। चूँकि 80% से अधिक बिक्री लाभ पर की गई थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कुल बिक्री की औसत बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है।

60. कीमत समायोजन की दावों के अनुसार अनुमति दी गई है। तदनुसार, सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>ख. निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

61. मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक होने के साथ-साथ निर्यातक भी है। जांच अवधि के दौरान, मेसर्स सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही हिरण्यवर्णम केमिकल्स के माध्यम से *** मीट्रिक टन और केमपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा *** मीट्रिक टन यूनीवर्ल्ड ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से 88,049 मीट्रिक टन वस्तु का निर्यात किया।

62. उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी मालभाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। उत्पादक/निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय माल भाड़ा, ऋण लागत, प्रहस्तन व्यय, कमीशन, बीमा और विदेशी माल भाड़ा के लिए समायोजन का दावा किया गया है। दावा किए गए समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। निर्यात कीमत और पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया जिस पर अंतिम निर्यातक ने भारत में असंबंधित ग्राहक को माल बेचा है। निर्यात कीमत को कारखाना-द्वार कीमत प्राप्त करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया गया था। चूँकि निर्यात के कई माध्यम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित किया गया है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>ईरान, तुर्की, रूस और अमेरिका के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

63. संबंधित देशों के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>ईरान, तुर्की, रूस और अमेरिका के सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

64. संबद्ध देशों के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत, नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

65. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। पाटन मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से निर्यात कीमत की तुलना हेतु सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है। भारित औसत पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	**उत्पादक का नाम**	**सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)**	**निवल निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन रेंज**
तुर्की						
1	तुर्किये सिसेवे कैम फैब्रिकालारि ए.एस., तुर्की	***	***	***	***	105-115
2	कज़ान सोडा एलेक्ट्रिकयूरेटिम ए. एस., तुर्की	***	***	***	***	80-90
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	140-150
रूस						
4	मैं. संयुक्त स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी (उत्पादक/निर्यातक,	***	***	***	***	130-140

	रूस)					
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	190-200
यूएसए						
6	मैं. सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	***	***	***	***	80-90
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	130-140
ईरान						
8	कोई	***	***	***	***	85-95

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. रूस से आयात में वृद्धि को बाजार की माँग में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। रूसी आयात में यह वृद्धि केवल बढ़ती माँग की प्रतिक्रिया है और घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत नहीं है।

ii. आयात में वृद्धि भारत में कुल माँग में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है और इसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में भारत में उत्पादकों के उत्पादन या बिक्री में कमी नहीं आई है।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 13% की वृद्धि हुई, जो आयात की उपस्थिति के बावजूद बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है।

iv. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में 147% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है, तो वह घरेलू प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण हुई है।

v. घरेलू उत्पादकों की क्षमता 2020-21 से 2022-23 और जांच की अवधि तक बढ़ी है, जो क्षति अवधि में 2% की संचयी वृद्धि दर्शाती है।

vi. घरेलू उत्पादकों के पीयूसी और एनपीयूसी का उत्पादन 2020-21 से 2022-23 और जांच की अवधि तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 20% की वृद्धि दर्शाता है। पीयूसी का उत्पादन भी 20% की वृद्धि दर्शाता है।

vii. स्थापित क्षमता में मामूली वृद्धि के बावजूद, 2020-21 से जांच की अवधि तक क्षमता उपयोग में 17% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक परिचालन दक्षता में सुधार और उत्पादन को अनुकूलित करने में सक्षम रहे हैं।

viii. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है, और रुझान उत्पादन की एक स्वस्थ और बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

ix. घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में 24% की वृद्धि हुई और घरेलू बिक्री में 13% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात बिक्री में 168% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो निर्यात बाजारों के प्रति रणनीति में बदलाव का संकेत है।

x. जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कम हुई है।

xi. निर्यात मात्रा में भारी वृद्धि दर्शाती है कि घरेलू बिक्री में कोई भी गिरावट या मंदी स्वेच्छा से रही है और आयात के कारण नहीं है। घरेलू उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वास्तविक क्षति का दावा कमजोर हो रहा है।

xii. औसत मालसूची को उत्पादन और बिक्री के प्रतिशत के रूप में माना जाना चाहिए, जो गिरावट दर्शाता है। यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक जो उत्पादित किया गया था उसे बेचने में सक्षम थे, जो किसी क्षति का संकेत नहीं देता है।

xiii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारकों की जाँच करें जिनके कारण उसके लाभ में भारी गिरावट आई है।

xiv. रोजगार में गिरावट और मजदूरी में वृद्धि को सीधे तौर पर संबद्ध आयातों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

xv. क्षति अवधि में उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जिसमें प्रति दिन उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई है और प्रति कर्मचारी और प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता में 23% की वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होने का संकेत देता है।

xvi. घरेलू उद्योग की औसत नियोजित पूंजी में 49% की वृद्धि हुई और कार्यशील पूंजी में 168% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। तथापि, निवल अचल संपत्तियों में केवल 33% की मामूली वृद्धि देखी गई। इन बढ़ोतरी के बावजूद, आरओआई में सकारात्मक रहते हुए भी 46% की उल्लेखनीय गिरावट आई। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे ऐसे अन्य कारकों की जाँच करें जो इस तरह के बदलावों में योगदान दे सकते हैं।

xvii. क्षति मूल्यांकन के लिए असामान्य वर्षों पर विचार किया गया है। 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण आयात प्रतिबंधित थे। इसके अलावा, 2022-23 में, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई।

xviii. आयात केवल भारत में मौजूद मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए किया गया था, जो घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए भारी निर्यात के कारण हुआ है।

xix. आयात कीमतों में कमी पाटन के कारण नहीं, बल्कि एक वैश्विक घटना के कारण है, जैसा कि सभी संबद्ध देशों के आयात कीमत में उतार-चढ़ाव से देखा जा सकता है। जांच की

अवधि के दौरान कीमतों में कमी आई, किंतु फिर भी आधार वर्ष की तुलना में अधिक बनी रही।

xx. घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमत में लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक दर से वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इस मामले में कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं है।

xxi. अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण जांच की अवधि से पहले की अवधि तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई।

xxii. शिपिंग उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण घरेलू उत्पादक बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक वृद्धि करने में सक्षम रहे, जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पादक कीमतें बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला संकट का अनुचित लाभ उठाते हैं।

xxiii. आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच की अवधि में केवल कुछ गिरावट के साथ सकारात्मक लाभ बनाए रखा है, जिसके बावजूद घरेलू उत्पादक लाभदायक बने रहे।

xxiv. घरेलू उद्योग ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान असाधारण लाभ वृद्धि हासिल की, जिससे लाभ में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई।

xxv. कीमतह्रास में वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग लगातार उपकरणों और सुविधाओं में निवेश कर रहा है, जो उस उद्योग के साथ असंगत है जो भौतिक क्षति का सामना कर रहा है।

xxvi. संबद्ध वस्तुओं के तीन प्रमुख उत्पादकों के समग्र वित्तीय आंकड़े पिछले पांच वित्तीय वर्षों में मजबूत लाभप्रदता की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

xxvii. क्षति मार्जिन की गणना के लिए मालभाड़ा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनुबंध III के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पिछले निर्णयों में इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया है। आवेदकों का दावा आर्थिक तर्क पर आधारित नहीं है और प्राधिकारी की दीर्घकालिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

कमतर शुल्क नियम पर भारत के पेपर का कोई भी संदर्भ गलत है और यह पेपर अनुबंध III की शुरूआत के काफी बाद विश्व व्यापार संगठन में प्रस्तुत किया गया था।

xxviii. क्षति-रहित कीमत निर्धारित करते समय आरएसपीएल के आबद्ध उत्पादन पर विचार करने के आवेदकों के अनुरोध को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल एनआईपी को बढ़ाने का अनुरोध है।

झ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

67. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान जाँच में संचयी मूल्यांकन उपयुक्त होगा और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी मूल्यांकन करें।

ii. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन का इतिहास रहा है।

iii. अल्पावधि में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, आयात मात्रा में 100% की वृद्धि हुई है, जबकि मांग में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 9% की वृद्धि हुई है।

iv. जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 234% और आधार वर्ष की तुलना में 99% की वृद्धि हुई, जो आयात में भारी वृद्धि दर्शाता है।

v. भारतीय उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2022-23 में क्रमशः 19% और 9% से बढ़कर जांच अवधि में 34% और 18% हो गया।

vi. सभी संबद्ध देशों में कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

vi. जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई; तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी।

viii. संबंधित आयातों के परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान कीमतों में भारी गिरावट आई है।

ix. आयातों का वर्तमान पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम है।

x. आयात की बढ़ी हुई मात्रा ने घरेलू बिक्री, मालसूची स्तरों और क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xi. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में 4% की गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग के लिए पाटित आयातों के कारण बिक्री में कमी आई।

xii. मालसूची में वृद्धि हुई और निर्यात में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग को परिचालन और लाभ बनाए रखने के लिए अपनी बिक्री को निर्यात बाजार की ओर ले जाना पड़ा है।

xiii. मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू बिक्री में गिरावट आई, जबकि आयात में वृद्धि हुई।

xiv. घरेलू उद्योग ने काफी बिक्री मात्रा गंवा दी, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

xv. बढ़ती मांग और बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी कम रहा है।

xvi. घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग दोनों ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को देखा है।

xvii. जांच की अवधि में आयात कीमतों में लागत में समान कमी के बिना भारी गिरावट आई है।

xviii. आयातों का भारित औसत पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। घरेलू उद्योग आयात की कीमतों से मेल खाने के प्रयास में अपने लाभ को कम करके घाटा उठा रहा है।

xix. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में 67% की गिरावट के साथ भारी गिरावट आई।

xx. जब 2022-23 में आयात की कीमतें अधिक थीं, तो घरेलू उद्योग ने इष्टतम निष्पादन किया; तथापि, आयात कीमतों में बाद की गिरावट के साथ निष्पादन खराब हो गया।

xxi. नकद लाभ ने भी यही प्रवृत्ति अपनाई, जो 2022-23 तक सुधरता रहा और फिर जांच की अवधि में तेजी से घट गया।

xxii. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के कारण मांग के अनुपात में बिक्री बढ़ाने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची स्तरों में मामूली वृद्धि हुई।

xxiii. निर्यात के अभाव में, घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई मालसूची या कम उत्पादन और उपयोग के माध्यम से अधिक गंभीर क्षति का सामना करना पड़ता।

xxiv. रोजगार और मजदूरी कई कारकों से प्रभावित होते हैं और केवल पाटन-संबंधी क्षति के संकेत नहीं हैं।

xxv. उत्पादकता का स्तर पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रहा है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान मात्रा मापदंडों में प्रतिकूल वृद्धि और कीमत मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है।

xxvii. आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और यदि उपचारात्मक शुल्क नहीं लगाए जाते हैं, तो तीव्र क्षति का एक विश्वसनीय खतरा मौजूद है।

xxviii. एनआईपी के निर्धारण के लिए "आबद्ध उपयोग" के लिए उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आबद्ध उत्पादन का उपयोग घरेलू खपत के लिए भी किया जाना है। यदि आरएसपीएल का एकीकरण नहीं हुआ होता, तो वर्तमान में आबद्ध उत्पादन के रूप में वर्गीकृत माल घरेलू बाजार में बेचा जाता। इसी प्रकार, आरएसपीएल की सोडा ऐश विनिर्माण क्षमता के अभाव में, घरेलू मांग वैकल्पिक उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती।

इसलिए, किसी भी परिदृश्य में, वर्तमान में आबद्ध मानी जाने वाली मात्रा समग्र घरेलू उत्पादन का हिस्सा होती।

xxix. आरएसपीएल की आबद्ध खपत, आबद्ध खपत नहीं है और इसे आबद्ध बिक्री माना जाना चाहिए। आरएसपीएल के वित्तीय रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि आरएसपीएल सोडा ऐश प्रभाग ने कंपनी के अन्य संयंत्रों को विभिन्न उत्पादों में उपयोग के लिए सोडा ऐश बेचा है और यह जारी किए गए बीजक और प्राप्त भुगतान से भी स्पष्ट होता है।

झ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

68. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मानदंडों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों को स्वतः ही संबोधित करता है।

69. पाटनरोधी अनुबंध II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के

लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

झ.3.1. संचयी मूल्यांकन

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II, पैरा (iii) के अनुसार, यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात के संबंध में एक साथ पाटनरोधी जाँच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:

क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

71. इस संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार अवलोकन करते हैं:

क. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है;

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है;

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल परस्पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

घ. आयातित और घरेलू उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।

72. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझते हैं।

झ.3.2. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

73. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के अंतिम पीयूसी पर आधारित आंकड़ों पर विचार किया है। पीयूसी की मांग इस प्रकार है:

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23(वा.)**	**पीओआई (वा.)**
मांग					
कुल आयात	एमटी	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
संबद्ध देश	एमटी	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
यूएसए	एमटी	1,95,753	81,801	1,12,924	2,20,990
तुर्की	एमटी				

		85,013	1,04,450	1,33,639	4,73,864
ईरान सहित संयुक्त अरब अमीरात से आयातित विषयगत वस्तुएं	एमटी	1,20,908	78,289	59,740	89,800
रूस	एमटी	87,836	51,867	71,194	1,09,976
अन्य देश	एमटी	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	23,64,267	27,44,305	27,17,923	26,80,153
अन्य की बिक्री	एमटी	23,651	41,683	58,430	58,430
आबद्ध बिक्री	एमटी	3,19,020	2,75,154	2,24,337	1,78,021
आबद्ध अंतरण	एमटी	2,05,016	2,66,065	2,99,378	3,15,655
कुल मांग	एमटी	36,03,876	38,60,017	39,35,955	42,49,426

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

74. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।

<u>झ.3.3. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

i. समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

75. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23**	**पीओआई**
संबद्ध देश से आयात	एमटी	4,89,511	3,16,407	3,77,496	8,94,630
अन्य देश	एमटी	2,02,411	2,16,404	2,58,391	1,22,536
कुल आयात	एमटी	6,91,922	5,32,811	6,35,887	10,17,166
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	17%	9%	11%	26%
भारतीय मांग (आबद्ध सहित)	%	14%	8%	10%	21%
भारतीय मांग (आबद्ध के बिना)	%	16%	10%	11%	24%
कुल आयात	%	71%	59%	59%	88%

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

76. यह देखा गया है कि आधार वर्ष 2021-22 से संबद्ध देशों से आयात में कमी आई, 22 अप्रैल-2023 के दौरान वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयात में 83% की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, जांच अवधि में संबद्ध आयात पिछले वर्ष, अर्थात् 22 अप्रैल-23 सितंबर, की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गए हैं।

77. जांच अवधि में भारतीय उत्पादन और उपभोग दोनों के संदर्भ में संबद्ध आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन और उपभोग के संदर्भ में आयात में पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में क्रमशः 15% और 11% अंकों की वृद्धि हुई है।

<u>झ.3.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

78. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती।

79. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के पंहुच मूल्य के साथ की गई है।

i. <u>कीमत कटौती</u>

80. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाज़ार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के पहुँच कीमत की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है। यह देखा गया है कि आयात बाज़ार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका कीमत कटौती को दर्शाती है:

विवरण	**यूओएम**	**यूएसए**	**तुर्की**	**ईरान सहित संयुक्त अरब अमीरात से आयातित विषयगत वस्तुएं**	**रूस**
पंहुच कीमत	रु./एमटी	21,987	20,334	21,245	21,599
	सूचीबद्ध	100	92	97	98
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	168	131	116

81. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तु के मामले में परिवहन लागत, उत्पादन लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, क्योंकि (क) घरेलू उद्योग गुजरात राज्य में स्थित है और बिक्री पूरे भारत में करनी होती है और (ख) उत्पाद की कीमत को देखते हुए, मालभाड़ा लागत उपभोक्ताओं की खरीद लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों के पहुँच कीमत से परिवहन लागत जोड़ने के बाद ही की जानी चाहिए। तथापि, विगत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने मालभाड़ा पर विचार किए बिना कीमत कटौती की सीमा की जाँच की। यह पाया गया है कि आयात, मालभाड़ा के साथ और उसके बिना, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में निर्यात भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों से कम कीमत पर किया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कटौती हुई है। कीमत कटौती

ने घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया है। कीमतों में कटौती लागत में कमी से अधिक रही है।

ii. <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

82. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में जानकारी प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	159	149
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	189	138
पंहुच कीमत	रु./एमटी	16,948	18,075	33,508	21,515
	सूचीबद्ध	100	107	198	127

83. यह देखा गया है कि 22 अप्रैल से 23 सितंबर की अवधि तक बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई, और बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतें 22 अप्रैल से 23 सितंबर तक कम या न्यूनीकृत नहीं हुईं। तथापि, पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई, किंतु बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी। यह देखा गया है कि आयातों की पहुँच कीमत में भी यही

प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रकार, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। संबद्ध आयात घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण कीमत न्यूनीकरण का कारण बन रहे हैं।

<u>झ.3.5. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड</u>

84. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और उचित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

85. आवेदक के जांच अवधि में कार्यनिष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उसके कार्यनिष्पादन से की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

86. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	4,089,200	4,089,200	4,189,200	4,189,200
	सूचीबद्ध	100	100	102	102

कुल उत्पादन	एमटी	2,916,407	3,452,880	3,506,194	3,505,500
	सूचीबद्ध	100	118	120	120
क्षमता उपयोग	%	71%	84%	84%	84%
	सूचीबद्ध	100	118	117	117
घरेलू बिक्रियॉ	एमटी	2,364,267	2,744,305	2,717,923	2,680,153
	सूचीबद्ध	100	116	115	113
आबद्ध बिक्रियॉ	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	70	56
निर्यात बिक्रियॉ	एमटी	166,753	235,368	212,094	447,616
	सूचीबद्ध	100	141	127	268
आबद्ध बिक्री सहित कुल	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	111	116

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

87. यह देखा गया है कि:

क. 22 अप्रैल-23 सितंबर की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई।

ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 22 अप्रैल-23 सितंबर की अवधि तक बढ़ा और उसके बाद जांच अवधि में स्थिर रहा।

ग. 2020-21 और 2021-22 के बीच घरेलू व्यापारिक बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, मांग में वृद्धि के बावजूद, उसके बाद जांच अवधि तक घरेलू व्यापारिक बिक्री में गिरावट आई है।

घ. चूँकि दो घरेलू उत्पादकों ने डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए अन्य इकाइयों को महत्वपूर्ण आबद्ध बिक्री की है, और चूँकि ये इन कंपनियों के दो प्रभागों के बीच बिक्री और खरीद के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसी आबद्ध बिक्री को पहले अलग-अलग रूप से और उसके बाद व्यापारिक बिक्री के साथ सामूहिक रूप से निर्धारित किया। यह देखा गया है कि 2021-22 में आबद्ध बिक्री और व्यापारिक बिक्री में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि तक गिरावट आई। यह भी देखा गया है कि सकल घरेलू व्यापारिक बिक्री और आबद्ध बिक्री में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है, अर्थात, इनमें 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि तक लगातार गिरावट आई। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में बिक्री की मात्रा में गिरावट का सामना करना पड़ा, चाहे आबद्ध बिक्री को शामिल किया जाए या नहीं। इसके अलावा, आबद्ध बिक्री भी जांच की अवधि में बिक्री की मात्रा में गिरावट दर्शाती है।

ड़. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उच्च स्तर पर है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उसे और अधिक उत्पादन और बिक्री करने से रोका गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन स्तर किसी भी स्थिति में उच्च स्तर पर है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

88. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा था:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	अप्रैल22-	पीओआई

				सित.23	
मांग में हिस्सा					
सभी आयात	%	22%	16%	19%	27%
संबद्ध देश	%	16%	10%	11%	24%
अन्य देश	%	7%	7%	8%	3%
घरेलू उद्योग	%	77%	83%	80%	71%
अन्य उत्पादक	%	1%	1%	2%	2%
कुल हिस्सा % में	%	100%	100%	100%	100%

नोट - 22 अप्रैल - 23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

89. संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में तेजी से घटी है। तथापि, उसके बाद जांच अवधि तक बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

90. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई। तथापि, उसके बाद जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी वैध हिस्सेदारी बनाए रखने से रोक दिया है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने मात्रा और बाजार हिस्सेदारी गंवा दी और उसे उत्पादन को कम लाभदायक निर्यात बिक्री में बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

91. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण किया गया है और वह निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23**	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	159	149
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	189	138
लाभ/घाटा	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	136	354	78
लाभ/घाटा	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	158	407	88
नकद लाभ (पीबीटी+मूल्यह्रास)	रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	129	305	91
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	150	351	103
पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	144	330	81
आरओआई	%	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	117	234	57

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

92. यह देखा गया है कि

क. जांच अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी। परिणामस्वरूप, जहाँ घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष से 22 अप्रैल-23 सितंबर तक बढ़ा, वहीं इस अवधि में आयात में तीव्र वृद्धि के साथ जांच अवधि में इसमें तीव्र गिरावट आई। जांच अवधि में लाभप्रदता अपने निम्नतम स्तर पर रही है।

ख. क्षति अवधि में, जहाँ बिक्री मात्रा में 13% की वृद्धि हुई, वहीं घरेलू बिक्री पर कर-पूर्व सकल लाभ में 12% की गिरावट आई।

ग. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में नकद लाभ में उल्लेखनीय गिरावट (70%) आई। इस अवधि में बिक्री के प्रति इकाई नकद लाभ में भी तीव्र गिरावट आई। क्षति अवधि में, घरेलू बिक्री में 13% की वृद्धि के बावजूद, बिक्री के प्रति इकाई नकद लाभ में 8% की गिरावट आई।

घ. निवेश पर आय (आरओआई) में लाभ और नकद लाभ के समान ही रुझान रहा। पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में कर-पूर्व लाभ में तीव्र गिरावट (76%) आई। क्षति अवधि के दौरान, कुल बिक्री पर ब्याज-पूर्व लाभ में 20% की गिरावट आई, जबकि बिक्री की मात्रा में 13% की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, जांच अवधि में निवेश पर आय में पूर्ववर्ती अवधियों और आधार वर्ष दोनों की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आई।

iv. मालसूची

93. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	260,972	155,080	101,801	240,287
	सूचीबद्ध	100	59	39	92
अंतिम मालसूची	एमटी	155,080	101,801	260,286	196,438
	सूचीबद्ध	100	66	168	127
औसत मालसूची	एमटी	208,026	128,441	181,044	218,362
	सूचीबद्ध	100	62	87	105

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

94. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर मार्च, 2022 तक कम हुआ है। तथापि, उसके बाद मालसूची के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद मालसूची में वृद्धि हुई है।

v. रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता

95. घरेलू उद्योग की रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल22-सित.23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3,921	4,014	3,834	3,824
	सूचीबद्ध	100	102	98	98

वेतन और मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	118	143	138
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	8,333	9,865	10,018	10,016
	सूचीबद्ध	100	118	120	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	744	860	915	917
	सूचीबद्ध	100	116	123	123

नोट - 22 अप्रैल-23 सितंबर और जांच अवधि के आंकड़े 12 महीनों के लिए वार्षिकीकृत हैं।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ी है और उसके बाद जांच अवधि तक कम हुई है। क्षति अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है, जबकि जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

vi. वृद्धि

97. यह देखा गया है कि आयातों के कारण मात्रा और कीमत दोनों मानकों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**अप्रैल22-सित.23**	**पीओआई**
उत्पादन	वर्षवार	-	18%	2%	0%
क्षमता उपयोग	वर्षवार	-	13%	-1%	0%
घरेलू बिक्री	वर्षवार	-	16%	-1%	-1%
मालसूची	वर्षवार	-	-38%	41%	21%

प्रति इकाई लाभ	वर्षवार	-	36%	159%	-78%
लाभ (लाख रुपये में)	वर्षवार	-	58%	157%	-78%
नकद लाभ (लाख रुपये में)	वर्षवार	-	50%	134%	-71%
आरओसीई	वर्षवार	-	3%	20%	-30%
बाजार हिस्सा-घरेलू उत्पादक	वर्षवार		5%	-2%	-9%

vii. घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

98. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, तथा पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे अन्य कारकों की जांच की है जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिससे कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

viii. पूंजी जुटाने की क्षमता

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहा है। संबद्ध वस्तुओं के पाटन से घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने नियोजित निवेश का दावा किया है, किंतु पाटित आयातों के कारण वे आगे

नहीं बढ़ पा रहे हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक पूंजी-प्रधान उत्पाद है और वर्तमान निवेश योजनाएँ *** करोड़ रुपये के सकल निवेश पर *** मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि के लिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि में अर्जित लाभ इस निवेश की पर्याप्त सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे।

ix. पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

100. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

ञ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)</u>

101. प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की भी जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या ये कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

102. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात कम मात्रा में या अधिक कीमत पर होता है। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है।

ख) माँग में संकुचन

103. क्षति अवधि के दौरान माँग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, माँग में गिरावट प्राधिकारी द्वारा पाई गई क्षति का कारण नहीं है।

ग) उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन

104. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

105. जाँच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है।

ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

106. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

107. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग मुख्यतः घरेलू बाजार में ही है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

108. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

<u>नुकसान और कारण-प्रभाव संबंध पर निष्कर्ष</u>

109. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है। डंपिंग वाले आयात और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच कारण-प्रभाव संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित है:

i. आयात संख्या और प्रतिशत दोनों में बढ़े हैं, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।

ii. संबंधित आयात का बाजार हिस्सा बढ़ा, जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया।

iii. घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट से क्षमता का कम उपयोग हुआ।

iv. संबंधित आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया, जिससे कीमतों में गिरावट आई। इसके बाद, घरेलू उद्योग को लाभ, कैश लाभ और निवेश पर रिटर्न में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा।

v. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ और निवेश पर रिटर्न में भारी गिरावट आई।

110. उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित देशों से भारत में संबंधित वस्तुओं के बढ़ते डंपिंग वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा है। संबंधित देशों से आने वाले या निर्यात किए गए संबंधित वस्तुओं के डंपिंग वाले आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच एक कारण-प्रभाव संबंध है।

ट. <u>क्षति मार्जिन</u>

111. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त पहुँच कीमत की तुलना हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत

निवल अचल संपत्तियाँ और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

112. प्राधिकारी क्षति मार्जिन निर्धारित करते समय माल भाड़े को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन के आकलन के लिए प्राधिकारी की सतत् परिपाटी, माल भाड़े के बिना पहुँच कीमत की तुलना एनआईपी के साथ समतुल्य स्तर पर करने की रही है। इस मामले में भी यही पद्धति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार कारखाना-द्वार स्तर पर किया गया है और इसकी तुलना पत्तन स्तर पर आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

113. ऊपर यथा निर्धारित पहुँच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	**उत्पादक का नाम**	**क्षतिरहित कीमत (यूएसडी/एमटी)**	**पंहुच मूल्य (यूएसडी/एम टी)**	**क्षति मार्जिन (यूएसडी/एम टी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन रेंज**
तुर्की						
1	तुर्किये सिसेवे कैम फैब्रिकलर ए.एस. तुर्की	***	***	***	***	0-10
2	डब्लू ई सोडा (ईटीआई +कजान)	***	***	***	***	30-40
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70

रूस						
4	मै. संयुक्त स्टाक कंपनी बशकीर सोडा कंपनी (उत्पादक/निर्यातक, रूस)	***	***	***	***	10-20
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
यूएसए						
6	मैं सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	***	***	***	***	10-20
7	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40
ईरान						
8	कोई	***	***	***	***	40-50

ठ. <u>क्षति का खतरा</u>

114. वर्तमान जाँच में, घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे का तर्क दिया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार, वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच की है, जिसमें निम्नानुसार बताया गया है:

"वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान या दूरगामी संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति

उत्पन्न होती हो जिसमें पाटन से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और वह आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है;

ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजार में पाटित निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा;

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा, और क्या इससे आगे के आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और

घ. जाँच की जा रही वस्तु की मालसूची।

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

115. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. खतरे के संबंध में किए गए दावे भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात के संदर्भ में नहीं हैं और यह इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि भारतीय माँग का लगभग 70-80% भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरा किया जाता है और शेष लगभग 20-30% आयात किया जाता है, वह भी तब जब देश में प्राकृतिक पद्धति से शून्य उत्पादन होता है।

ii. वैश्विक क्षमता और उत्पादन प्रवृत्तियाँ भारतीय बाजार के लिए खतरा सिद्ध नहीं करती हैं और घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पता चले कि संबद्ध देशों की अतिरिक्त क्षमता भारत पर लक्षित होगी।

iii. यह तथ्य कि संबद्ध देशों के उत्पादक निर्यात करते हैं, यह सिद्ध नहीं करता कि वे भारत को क्षतिकारी मात्रा या क्षतिकारी कीमतों पर अतिरिक्त निर्यात करेंगे।

iv. आवेदक ने नियमावली में यथा अभिज्ञात खतरे के चार कारकों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

i. वर्तमान जांच अवधि के दौरान आयात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।

ii. ये आयात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर किए गए हैं, जिनमें पाटित मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और काफी अधिक हैं।

iii. संबद्ध देशों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य क्षमताएँ हैं, जो भारतीय माँग से कहीं अधिक हैं।

iv. वैश्विक स्तर पर, सोडा ऐश का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और चीन में केंद्रित है, जिनकी संयुक्त रूप से वैश्विक क्षमता में 72% हिस्सेदारी है।

v. वर्तमान वैश्विक स्थापित क्षमता 75 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 65 मिलियन मीट्रिक टन की वैश्विक माँग से अधिक है।

vi. संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता 14 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें अतिरिक्त 5 मिलियन मीट्रिक टन की घोषणा की गई है और तुर्की के पास 5 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 400,000 मीट्रिक टन की नियोजित वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप 8 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित निवल वैश्विक क्षमता वृद्धि होगी।

vii. वर्तमान में, 4 से 5 मिलियन मीट्रिक टन की अधिशेष वैश्विक क्षमता है, जो भारत की कुल मांग के बराबर है और इसके जारी रहने की आशा है।

viii. तुर्की का एक प्रमुख उत्पादक, ईटीआई सोडा, सिनेर समूह का हिस्सा है, जो अमेरिका में भी कार्यरत है। चूँकि वर्तमान अमेरिकी निर्यात पूरी तरह से इसी समूह से हैं, इसलिए अमेरिकी निर्यात को प्रभावी रूप से तुर्की निर्यात माना जा सकता है।

ix. यूरोप, लैटिन अमेरिका और अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में हाल ही में नकारात्मक खपत वृद्धि देखी गई है:

x. वैश्विक स्तर पर घटती मांग और क्षमता विस्तार के कारण वैश्विक स्तर पर अतिआपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

xi. बाजार रिपोर्टें मांग स्थिरता के लिए खतरों को उजागर करती हैं, जो रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनावों से और बढ़ गए हैं।

xii. आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक मांग में गिरावट आई है, प्रचालन दरें 2022 में अधिकतम होंगी और 2023 में घटेंगी, और 2024 में और गिरावट की उम्मीद है।

क्र.सं.	बाजार	वृद्धि
1	यूरोप	-4%

2	लैटिन अमरीका	-7%
3	यूएस	-10%
4	भारत	1%
5	संचयी	-2%

xiii. भारत बढ़ती माँग वाले कुछ बाज़ारों में से एक बना हुआ है, जो इसे अधिशेष वैश्विक आपूर्ति के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है।

xiv. वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति और कमज़ोर माँग के बावजूद, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमता वृद्धि जारी है, ।

xv. भारत को छोड़कर, वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति और घटती माँग के बीच असंतुलन, कीमतें उत्पादन लागत से कम होने पर, संयंत्रों के बंद होने का जोखिम बढ़ाता है।

xvi. तुर्की के उत्पादकों ने कमजोर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग के बावजूद क्षमता का विस्तार किया है।

xvii. सिनेर ने 400,000 मीट्रिक टन क्षमता जोड़ी; तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में प्रचालन करने वाली डब्लूई सोडा की भी विस्तार योजनाएँ चल रही हैं।

xviii. कमजोर यूरोपीय माँग के कारण तुर्की से यूरोप को निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

xix. कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय माँग के कारण व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, और निर्यातक क्षमताओं के विस्तार से यह और भी बदतर हो गया है।

xx. निर्यात बाज़ारों में आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण नई क्षमता की योजना बनाई गई थी, तथापि कोविड-19 के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई।

xxi. अमेरिका की कुल क्षमता 14 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता की घोषणा की गई है।

xxii. निर्यात के अवसरों को सीमित करने वाली कमजोर अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण वास्तविक उत्पादन अभी तक नई क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाया है।

xxiii. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, अगस्त 2023 का उत्पादन 869,000 मीट्रिक टन था, जो जुलाई और अगस्त 2022 की तुलना में 8% कम है।

xxiv. जनवरी 2023 से अगस्त 2023 की अवधि में उत्पादन 7.23 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3% कम है।

xxv. अमेरिकी उत्पादक भारत जैसे बाजारों में अधिशेष स्टॉक बेचने का प्रयास करके वैश्विक अतिआपूर्ति और कमजोर मांग की प्रतिक्रिया कर रहे हैं।

xxvi. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, जांच अवधि के दौरान अमेरिका से भारत में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और कम से कम 30% अमेरिकी क्षमता अप्रयुक्त रह गई।

xxvii. संबद्ध देशों के उत्पादक अपनी अत्यधिक क्षमताओं के कारण अत्यधिक निर्यात-उन्मुख हैं।

xxviii. पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में, इन देशों के निर्यातकों द्वारा अल्प समयावधि में भारत को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने की संभावना है।

xxix. घटती माँग और निरंतर क्षमता विस्तार से प्रेरित वैश्विक अतिआपूर्ति, भारतीय उद्योग के लिए वास्तविक क्षति का स्पष्ट खतरा उत्पन्न करती है।

xxx. भारत की बढ़ती माँग इसे अधिशेष निर्यात का प्रमुख लक्ष्य बनाती है, जिससे मौजूदा चुनौतियों के बावजूद क्षति का जोखिम बढ़ जाता है।

xxxi. जाँच अवधि के दौरान आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, और पंहुच कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से काफी कम हो गई हैं।

xxxii. कम कीमत वाले आयात घरेलू बाजार कीमतों को कम कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम पर हुए हैं, जिससे स्थानीय कीमतों पर भारी गिरावट का दबाव पड़ रहा है।

xxxiii. कमज़ोर घरेलू कीमतों के कारण आयात की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान और भी बदतर हो सकता है।

xxxiv. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त विनिर्माण क्षमता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

xxxv. मौजूदा क्षमता से पता चलता है कि विदेशी उत्पादक कम समय में आपूर्ति की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे घरेलू बाजार की स्थिरता के लिए संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है।

xxxvi. घरेलू उद्योग ने हाल की अवधि में मालसूची के स्तर में तेज वृद्धि को देखा है, जो संभावित बाजार संतृप्ति का संकेत देता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

117. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जाँच के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार प्राधिकारी को यह जॉच परिणाम दर्ज करना आवश्यक है कि भारत में आयातित पदार्थ भारत में किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचा रहे हैं या क्षति पहुँचाने की खतरा बने हुए हैं या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा डाल रहे हैं। चूँकि प्राधिकारी यह निष्कर्ष करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, इसलिए उनका क्षति की जाँच केवल घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तक ही सीमित रखी जाए।

ड. <u>भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे</u>

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

i. सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।

ii. सोडा ऐश पर कोई भी एडीडी औद्योगिक कीमत श्रृंखला को बाधित करेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को कमजोर करेगा।

iii. घरेलू उद्योग को पहले से ही न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के माध्यम से सुरक्षा का लाभ मिल रहा है; अतिरिक्त शुल्क अत्यधिक सुरक्षा उपाय होंगे।

iv. एडीडी के और अधिक लगाए जाने से कांच निर्माण जैसे प्रमुख उद्योग अलाभकारी हो सकते हैं, जिसके घरेलू उत्पादन और रोजगार पर संभावित दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

v. भारतीय सोडा ऐश उत्पादक ऐतिहासिक रूप से व्यापार सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहे हैं, जबकि अब घरेलू बाजार में उनकी हिस्सेदारी 70% से अधिक है; वर्तमान बाजार प्रभुत्व के अंतर्गत भी ऐसी निर्भरता जारी है।

vi. सोडा ऐश के लिए मांग-आपूर्ति संतुलन अभी भी संतुलित बना हुआ है, जिससे औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करना आवश्यक हो गया है; क्षति अवधि के दौरान, आयात 5-10 लाख मीट्रिक टन के बीच रहा, जबकि कुल मांग 40-43 लाख मीट्रिक टन थी।

vii. प्राकृतिक तरीके से उत्पादित सोडा ऐश की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आयात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि काफी अधिक टिकाऊ है और घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त सिंथेटिक मार्ग से प्रति टन 1 टन सीओ2 की तुलना में 0.30 से 0.70 टन सीओ2 उत्सर्जित करता है।

viii. प्राकृतिक सोडा ऐश के आयात को प्रतिबंधित करने से भारत में टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि प्रस्तावित एडीडी से प्रयोक्ता लागत

में 2-5% की वृद्धि होगी, जिसका घरेलू उत्पादकों के लिए क्षतिकारी कीमत निर्धारण के साक्ष्य के बिना, मार्जिन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

ङ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. भारतीय उद्योग के हितों और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. संबद्ध वस्तुएँ पहले पाटनरोधी उपायों के अधीन थीं, और ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि पहले लगाए गए शुल्कों का अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

ii. भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आने वाले आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होती हैं, जिससे उद्योग को भारी क्षति हो रही है।

iii. उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करने, घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता का संरक्षण करने और भारत को विचाराधीन उत्पाद के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

iv. पाटनरोधी उपाय उचित मूल्यों पर उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करते हैं।

v. केवल आयात पर निर्भरता उपभोक्ताओं को उच्च मालसूची स्तर बनाए रखने के लिए बाध्य करेगी, जबकि घरेलू उत्पादकों से खरीद अधिक कुशल मालसूची प्रबंधन को संभव बना देती है।

vi. एक उचित और प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण बनाए रखने के लिए एक मजबूत घरेलू उद्योग आवश्यक है, जो अन्यथा पाटित आयातों से प्रभावित होगा।

vii. विचाराधीन उत्पाद के मज़बूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना जनता के हित में है।

viii. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोज़गार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में योगदान देता है।

ix. यदि घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान का समाधान नहीं किया जाता है, तो निरंतर उत्पादन अस्थाई हो सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक उद्देश्य कमज़ोर हो सकते हैं।

x. भारतीय सोडा ऐश उद्योग ने निरंतर वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसकी क्षमता 1998-99 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 4.5 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जो राष्ट्रीय माँग के अनुरूप है।

xi. उद्योग ने अतिरिक्त 2 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता विस्तार की योजना बनाई है, जो आत्मनिर्भरता और घरेलू आपूर्ति सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

xii. क्षमता वृद्धि के साथ-साथ रोज़गार में भी वृद्धि हुई है, और आगे के विस्तार को *** मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने के लिए *** करोड़ रुपये के नियोजित निवेश द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

xiii. तथापि, वर्तमान बाज़ार स्थितियों ने इन प्रस्तावित निवेशों की व्यवहार्यता को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल दिया है।

xiv. घरेलू सोडा ऐश उद्योग रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पूरे भारत में लगभग 22,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।

xv. गुजरात, एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में, इस रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।

xvi. पाटनरोधी शुल्क लगाना न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय हित में भी है।

xvii. ऐसे उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग का संरक्षण नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है।

xviii. ये कार्य भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देते हैं।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबंधित देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार को विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। साथ ही, प्राधिकारी इस बात से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, शुल्क लगाने से देश में नए उत्पादकों के उभरने को प्रोत्साहन मिल सकता है।

121. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के बारे में संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के

संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, घरेलू उद्योग की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं।

122. सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में हो रहे पाटन को कम करना, उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करना और घरेलू विनिर्माण की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पिछले शुल्कों के बावजूद, अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है, और घरेलू उद्योग ने विकास प्रदर्शित किया है, 1998-99 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से 2023-24 में 4.5 मिलियन मीट्रिक टन तक क्षमता का विस्तार किया है, और आगे निवेश की योजना है। ये उपाय भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से जब पाटित वस्तु की कीमत घरेलू बिक्री लागत से कम होती है, जिससे वास्तविक क्षति होती है। एक मजबूत घरेलू उद्योग न केवल उपभोक्ताओं के लिए कुशल मालसूची प्रबंधन में सहायक होता है, बल्कि 22,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है।

123. भारत में काँच उद्योग पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि सोडा ऐश पर शुल्क लगाने से इसकी लागत पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के काँच उत्पादों पर एडीडी लगाकर पहले ही पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों से पता चलता है, ग्यारह अलग-अलग मामले सामने आए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के काँच पर शुल्क लगाए गए हैं, जो काँच उद्योग के घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए निरंतर समर्थन को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, सोडा ऐश पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क से लागत में व्यवधान उत्पन्न होने या डाउनस्ट्रीम कीमत श्रृंखला पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

124. यह नोट किया जाता है कि कुछ आवेदक कंपनियाँ देश में डिटर्जेंट के उत्पादन में भी कार्यरत हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत कीमत के उतार-चढ़ाव के विश्लेषण से पता चलता है कि सोडा ऐश की आयात कीमतों में गिरावट के बावजूद, डिटर्जेंट की कीमतों में आनुपातिक रूप से कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि डिटर्जेंट की कीमतें सोडा ऐश की कीमतों में उतार-चढ़ाव से सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, जो डाउनस्ट्रीम बाजार में कीमत निर्धारण में एक सीमा तक अलगाव या स्वतंत्रता का संकेत देता है। इसके अलावा, डिटर्जेंट की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव पर विचार करते समय, सोडा ऐश और अन्य प्राथमिक कच्ची सामग्री - जो कि लीनियर एल्किलबेंजीन (एलएबी) है - की कीमतों का अनुमान घरेलू उद्योग द्वारा लगाया गया है। अप्रैल 2020 से एक तुलनात्मक आकलन से पता चलता है कि जब एलएबी और सोडा ऐश की कीमतों में वृद्धि हुई, तो डिटर्जेंट की कीमतें भी बढ़ीं। तथापि, जब इन कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई, तो डिटर्जेंट की कीमतें स्थिर रहीं और उनमें कोई खास कमी नहीं देखी गई। इस प्रकार, कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव का डिटर्जेंट की कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

125. व्यापक होते हुए व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी सहित मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर निर्भरता को मजबूत करना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति का कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। शुल्क लगाने से समान अवसर सृजित होने की उम्मीद है। शुल्क लगाना विशेष रूप से निर्यात पर उच्च निर्भरता को देखते हुए, अंतिम प्रयोक्ताओं के हित में माना जाता है।

126. पाटनरोधी शुल्क, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की नीति को सुदृढ़ करके, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे। अतिरिक्त शुल्क, ₹1,200 करोड़ रुपये के नियोजित निवेश द्वारा समर्थित, घरेलू क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करेंगे और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देंगे। एक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार को बढ़ावा देकर, शुल्कों को लागू करना आर्थिक विकास,

आपूर्ति सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के अनुरूप है, और इससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों या उपभोक्ता मार्जिन को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं होगा।

127. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएँगे, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी, और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सामान्यतः, पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे, और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ढ. <u>प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ</u>

ढ.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

128. प्रकटीकरण वक्तव्य पर अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

i. प्राकृतिक सोडा ऐश को शामिल न करने तथा प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच अदला-बदली की मौजूदगी के बारे में प्राधिकरण का अवलोकन गलत है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रियाओं, लागत संरचनाओं और पर्यावरणीय प्रभाव में स्पष्ट अंतर है।

ii. हल्का और सघन सोडा भी अलग-अलग उत्पाद हैं और अलग-अलग HSN कोड के अंतर्गत आते हैं। हल्के सोडा ऐश का इस्तेमाल विशेष रूप से डिटर्जेंट निर्माता करते हैं क्योंकि प्राकृतिक सोडा ऐश में अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं।

iii. टाटा केमिकल्स और निरमा के बीच संबंधित पक्षकार संबंध के आधार पर पात्रता के प्रश्न को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच की अवधि के दौरान मात्राएँ नगण्य थीं। दोनों संस्थाओं के बीच संबंध इस तथ्य से पुष्ट होता है कि उनके सहयोगियों द्वारा निर्यात प्रारंभिक अवधि में हुआ था।

iv. पहले से मौजूद एमआईपी के अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना उपयोगकर्ताओं और आयातकों के लिए दोहरी तलवार होगी, क्योंकि एमआईपी को कम कीमत वाले आयातों की जांच के लिए एक वैध और पर्याप्त उपाय माना जाता है।

v. घरेलू उद्योग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ("क्यूसीओ") और अनिवार्य बीआईएस मानक जारी करने के लिए एक अन्य मंच में दायर आवेदन भी लंबित है। इसलिए, घरेलू उद्योग को डीजीटीआर से संपर्क करने से पहले मंच के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था।

vi. विषयगत जाँच में 9 महीने की जाँच अवधि (POI) की अनुमति देने का कोई औचित्य रिकॉर्ड में नहीं है। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के साथ जाँच अवधि की तुलना करने पर प्रतिकूल क्षति विश्लेषण प्राप्त होगा क्योंकि ये वर्ष आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, कोविड-19, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष से चिह्नित थे, जिससे तुलना अविश्वसनीय हो जाती है।

vii. दायर याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई थी, जिससे व्यापार नियमावली और व्यापार सूचना 10/2018 के नियम 7 का उल्लंघन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और लागत संबंधी आँकड़े या तो रोक दिए गए थे या केवल अनुक्रमित रूप में उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन संशोधित आँकड़े काफी देरी से उपलब्ध कराए गए, जिससे इच्छुक पक्ष इस पर सार्थक टिप्पणियाँ देने में असमर्थ रहे।

viii. याचिकाओं के बंद हो जाने तथा घरेलू उद्योग द्वारा एंटी-डंपिंग कार्यवाही का आदतन सहारा लेने को देखते हुए, अब एंटी-डंपिंग संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, भले ही कोई क्षति न हुई हो।

ix. घरेलू उद्योग को संबंधित आयातों के कारण कोई भौतिक क्षति नहीं हो रही है। देश में मांग-आपूर्ति का अंतर लगातार बना हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात करने के निर्णय से यह अंतर और भी बढ़ गया है।

x. घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य 2022-23 तक बिक्री लागत से काफी ऊपर बढ़ गया है और जाँच अवधि में अनुक्रमित लागत स्तरों से ऊँचा बना हुआ है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक लाभप्रदता भी अर्जित की है, और जाँच अवधि में लाभ में गिरावट केवल आपूर्ति व्यवधानों के दौरान अप्रत्याशित लाभ के बाद सामान्यीकरण के कारण है। यहाँ तक कि इन्वेंट्री स्तर में वृद्धि भी नगण्य है और सितंबर 2023 में समापन इन्वेंट्री और अक्टूबर 2023 में आरंभिक इन्वेंट्री के बीच एक विसंगति है। वैश्विक और भारतीय कीमतों के बीच सहसंबंध दर्शाता है कि घरेलू मूल्य परिवर्तन बाजार द्वारा संचालित होते हैं।

xi. घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति के बीच भारी अंतर होने के कारण उपयोगकर्ता उद्योग पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो एंटी-डंपिंग शुल्क लगने से और भी बढ़ जाएगा क्योंकि डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए आयात पर निर्भर रहना बेहद महंगा पड़ेगा। एंटी-डंपिंग शुल्क लगने की स्थिति में डिटर्जेंट निर्माताओं पर इसका मात्रात्मक प्रभाव भी काफी होगा और लगभग 3.49% तक पहुँच जाएगा। निर्यातोन्मुखी आसियान देशों द्वारा दी जा रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, जो भारतीय बाजार की तुलना में बहुत कम कीमत पर डिटर्जेंट बेचते हैं, यह डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।

xii. सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों के तहत, आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है ताकि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद पर उनका वित्तीय बोझ कम किया जा सके। ये सुधार, अगर पीयूसी पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया जाता है, तो बेकार हो जाएँगे। डिटर्जेंट का इस्तेमाल लोग रोज़ाना करते हैं, और अगर उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर शुल्क लगा दिया जाता है, तो अंतिम उत्पाद, यानी डिटर्जेंट, की लागत वैसे भी बढ़ जाएगी और उस पर जीएसटी कटौती का असर खत्म हो जाएगा।

xiii. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने पर, यह संभावना है कि पीयूसी के घरेलू उत्पादक अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों में संशोधन करेंगे। आयातों से प्रतिस्पर्धी दबाव के अभाव में, घरेलू उद्योग पीयूसी की बिक्री कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप बाजार कीमतों

में सामान्य रूप से वृद्धि होगी, जिसका असर एजीआई सहित सोडा ऐश के सभी खरीदारों पर पड़ेगा।

xiv. एजीआई ने हाल ही में निर्यात पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र की पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया है। सोडा ऐश पर किसी भी प्रकार का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से एजीआई की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और निर्यात बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। यह एजीआई के व्यावसायिक हितों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि होगी, चाहे एजीआई प्राकृतिक सोडा ऐश का आयात करे या घरेलू उत्पादकों से सिंथेटिक सोडा ऐश खरीदे।

xv. सिंथेटिक सोडा ऐश का कार्बन फुटप्रिंट कम से कम 1.3 CO2/Mt होता है, जबकि प्राकृतिक सोडा ऐश का कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम यानी लगभग 0.4 CO2/Mt होता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ("CPCB") डिटर्जेंट उद्योग के लिए उत्सर्जन और अपशिष्ट जल मानक निर्धारित करता है, जो वास्तव में कम ग्रीनहाउस गैस ("GHG") उत्सर्जन वाले उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

xvi. सिंथेटिक लाइट/घने सोडा ऐश और प्राकृतिक घने सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 20% से अधिक है, जबकि सिंथेटिक लाइट और प्राकृतिक घने सोडा ऐश के बीच कीमत का अंतर 10% से अधिक है।

xvii. विगत में, प्राधिकरण ने इस बात की जाँच की थी कि क्या संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंधों के कारण अलग ढंग से कार्य किया है या डंपिंग प्रथाओं में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं जिनके परिणामस्वरूप स्वयं को क्षति पहुँची होगी। हालाँकि, वर्तमान जाँच में, प्राधिकरण ने उपरोक्त कारकों पर विचार नहीं किया है, सिवाय इस आकलन के कि टाटा और निरमा द्वारा पीयूसी का आयात काफी कम है।

xviii. प्राधिकरण ने भारतीय उत्पादन और कुल आयात के सापेक्ष संबंधित पक्षों से आयात का प्रतिशत प्रकट नहीं किया है। यह दृष्टिकोण प्राधिकरण की स्थापित पद्धति से विचलन दर्शाता है।

xix. बिक्री मूल्य, पीबीआईटी, मूल्यह्रास आदि से संबंधित जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह जानकारी उपलब्ध न कराने से इच्छुक पक्षों की उस पर सार्थक टिप्पणी करने की क्षमता बाधित होती है। घरेलू उद्योग को विषयगत जाँच में शामिल अन्य इच्छुक पक्षों की

तुलना में पारदर्शिता के किसी भिन्न या निम्नतर मानक पर नहीं रखा जा सकता, जिन्हें निर्धारित प्रारूपों का पालन करना आवश्यक है।

xx. ₹20,108/एमटी के एमआईपी का असर पहले ही बाज़ार की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में पड़ चुका है। एमआईपी के अतिरिक्त किसी भी तरह का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप अत्यधिक और अनुचित संरक्षण प्राप्त होगा। इस तरह के अति-मुआवजे का वित्तीय बोझ अंततः उपयोगकर्ताओं पर ही पड़ेगा।

xxi. एमआईपी का मूल उद्देश्य कम कीमत वाले आयातों पर प्रतिबंध लगाकर कथित क्षति को कम करना और इस प्रकार घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना था। हालाँकि, एमआईपी द्वारा अपनी लाभप्रदता में कोई ठोस सुधार लाने में विफलता इस मूल धारणा को कमजोर करती है कि आयात ही कथित क्षति का कारण है।

xxii. प्रकटीकरण विवरण में जांच अवधि के लिए 9 महीने की अवधि पर विचार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अवधि से अधिक लंबी जांच अवधि अपनाने के प्राधिकरण के निर्णय के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है कि क्या वह अवधि प्रतिनिधि और उपयुक्त है।

xxiii. पिछली जांच में प्राधिकरण ने न केवल नौ महीने की अवधि को जांच की अवधि मानने के कारण बताए थे, बल्कि इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां भी आमंत्रित की थीं।

xxiv. 6 माह और 9 माह की अवधि बहुत छोटी है तथा प्राधिकरण के लिए पाटन, क्षति और कारणता तथा भारतीय घरेलू बाजार की स्थिति का उचित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

xxv. याचिका में उल्लिखित 6 माह तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचाराधीन 9 माह में, घरेलू उद्योग के एक घटक अर्थात टाटा केमिकल्स लिमिटेड को उपयोगिता संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा प्रभावित हुई।

xxvi. उपयोगकर्ता नोट करता है कि पाटन मार्जिन तालिका में "अन्य सभी" के लिए मार्जिन शामिल नहीं है। यह एक आवश्यक तथ्य है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम

निष्कर्ष जारी करने से पहले "अन्य सभी" दरों के लिए मार्जिन प्रदान करते हुए एक संशोधित प्रकटीकरण विवरण जारी करें।

xxvii. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती निर्धारित करें ताकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। जिस मूल्य पर एचयूएल ने पीयूसी प्राप्त किया है, वह उन मूल्यों से बहुत अधिक है जिन पर एचयूएल ने आयात स्रोतों से पीयूसी प्राप्त किया था।

xxviii. जीएचसीएल, जो भारत में पीयूसी के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, द्वारा प्रकाशित वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के आधार पर, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ दर्ज किया गया है।

xxix. घरेलू उद्योग को क्षति (यदि कोई हो) संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है:

xxx. कम उत्पादन। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने आय सम्मेलन कॉल में स्वीकार किया कि पूंजीगत उपकरणों के टूटने के कारण क्षति अवधि के दौरान उनका उत्पादन कम था, और यह अपनी स्थापित क्षमता के तीन-चौथाई पर संचालित हुआ। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने उल्लेख किया कि उत्पादन रुकने और अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के कारण यह जांच की अवधि के दौरान समान क्षमता स्तर पर काम करता रहा। जैसा कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए अपने आय कॉल में स्वीकार किया है। इसी तरह की उपयोगिता-संबंधी सीमाओं ने जांच की अवधि के दौरान टाटा केमिकल्स लिमिटेड के उत्पादन की मात्रा को प्रभावित किया। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने आय कॉल में इसे स्वीकार किया।

xxxi. आयात कीमतों में यह अस्थायी गिरावट आयात कीमतों में वास्तविक कमी के बजाय, डाउनस्ट्रीम उत्पाद उद्योग में व्याप्त उथल-पुथल के कारण थी। आयात कीमतों में इस गिरावट के मूल कारणों को जीएचसीएल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

xxxii. प्रकटीकरण विवरण में दर्ज आंकड़ों और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं।

xxxiii. प्राधिकरण को एनआईपी के प्रयोजनों के लिए नियोजित पूंजी का निर्धारण करते समय उच्च निवल अचल परिसंपत्तियों के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

xxxiv. डिटर्जेंट उद्योग पिछले चार वर्षों में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ("आसियान") के सदस्य देशों, विशेष रूप से इंडोनेशिया, से डिटर्जेंट के आयात में भारी वृद्धि के दबाव से पहले से ही जूझ रहा है। शुल्क लगने के कारण सोडा ऐश की लागत में कोई भी वृद्धि डिटर्जेंट उत्पादकों के संचालन पर गहरा प्रभाव डालेगी।

xxxv. प्रकटीकरण विवरण में दर्ज मार्जिन के आधार पर शुल्कों के प्रभाव का परिमाणन: एंटी-डंपिंग शुल्कों का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि यह मात्र 0.46% है।

xxxvi. व्यापार सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण तैयार करना नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, यदि कोई हो, का निवारण करना है।

xxxvii. 12 महीने से कम की POI स्वार्थपूर्ण है और इसे विशेष रूप से एक गैर-मौजूद क्षति को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है।

xxxviii. प्रकटीकरण विवरण में दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि POI को विशेष रूप से केवल उन महीनों/अवधि को शामिल करके तैयार किया गया है, जब कीमतें कम थीं।

xxxix. प्रतिवादी का दावा है कि 12 महीने से कम अवधि के पी.ओ.आई. का चयन करना ए.डी.डी. नियमों के नियम 5(3 ए)(ii) का उल्लंघन है।

xl. प्रकटीकरण विवरण में, सितंबर 2023 के बाद आयात कीमतों में गिरावट और मात्रा में वृद्धि का हवाला देते हुए, संक्षिप्त जांच अवधि को उचित ठहराया गया है। यह औचित्य त्रुटिपूर्ण और चालाकीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें क्षति को मनगढ़ंत बनाने के लिए चुनिंदा रूप से कम कीमतों वाले महीनों को शामिल किया गया है।

xli. ये औचित्य प्रतिवादी को प्रकटीकरण विवरण चरण में ही बताए गए, जिससे उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार का पूर्वव्यापी तर्क प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है और नियम 5(3 ए)(ii) की स्पष्ट भाषा और आशय का खंडन करता है।

xlii. यह दावा कि POI विचलन के कारणों को आरंभिक नोटिस में शामिल करना आवश्यक नहीं है, गलत है और हितधारकों की भागीदारी को कमज़ोर करता है। प्रतिवादी का तर्क है कि जाँच क्षेत्राधिकार संबंधी कमियों से ग्रस्त है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

xliii. प्रतिवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवेदन और आरंभिक अधिसूचना व्यापार नोटिस संख्या 2/2004 का उल्लंघन करती है, जिसमें पी.ओ.आई. और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों को शामिल करना अनिवार्य है।

xliv. सेल बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यापार सूचनाएँ बाध्यकारी हैं और यदि वे त्रुटिपूर्ण हैं तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए–उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। व्यापार सूचना से प्राधिकरण का चयनात्मक विचलन पक्षपातपूर्ण और अनुचित प्रतीत होता है।

xlv. कांच उद्योग में गड़बड़ी के कारण संबंधित वस्तुओं की मांग में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप आयात कीमतों में गिरावट आई।

xlvi. घरेलू उद्योग ने प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन लिए बिना व्यापार नोटिस संख्या 2/2004 से एकतरफा विचलन किया।

xlvii. प्राधिकरण के कार्योत्तर तर्क में पूर्व विचार का अभाव है तथा यह पूर्वव्यापी युक्तिकरण के समान है।

xlviii. व्यापार नोटिस में संशोधन किए बिना इस विचलन का समर्थन करने से प्रक्रियागत विकृति उत्पन्न होती है तथा पूर्वाग्रह का खतरा पैदा होता है।

xlix. नियम 2(ख) विषयगत वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने से अयोग्य घोषित करता है। प्रकटीकरण विवरण में निर्यात मात्रा पर अनुचित रूप से विचार किया गया है, जो नियम 2(ख) के अंतर्गत अप्रासंगिक है। टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड को उनके संबंधित पक्ष निर्यातों के बावजूद शामिल करना नियम का उल्लंघन करता है और क्षति विश्लेषण को अमान्य बनाता है।

l. ऐसा प्रतीत होता है कि निरमा लिमिटेड द्वारा संबंधित पक्ष निर्यात की अवधि को बाहर करने के लिए जांच अवधि और क्षति अवधि को चुनिंदा रूप से परिवर्तित किया गया है।

li. साक्ष्य से पता चलता है कि निर्यात जुलाई-सितंबर 2023 में हुआ था, जिसे POI से बाहर रखा गया था और पिछले वर्ष में जोड़ा गया था।

lii. आवेदक ने अनिवार्य प्रमाणन या प्राधिकरण के बिना विस्तारित POI (अक्टूबर 2023-अप्रैल 2024) के लिए अद्यतन चोट डेटा प्रस्तुत किया।

liii. नियम अपूर्ण सूचना को, विशेष रूप से गोपनीयता दावों के अंतर्गत, टुकड़ों में सुधारने की अनुमति नहीं देते।

liv. घरेलू उद्योग का मूल्यह्रास काफी बढ़ गया है। एनआईपी के लिए 22% आरओसीई में कानूनी औचित्य और तर्कसंगतता का अभाव है।

lv. आर्थिक कारक और सूचकांक क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाते हैं

lvi. ईटीआई सोडा और संबंधित कंपनी कज़ान के लिए भूमि मूल्य की गणना डीएस बनाम दावे में भिन्न है।

lvii. डिटर्जेंट पाउडर की कीमत सोडा ऐश और एलएबी की बढ़ी हुई कीमतों के बराबर नहीं बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए निर्माताओं को सोडा ऐश और एलएबीएसए की अत्यधिक ऊँची कीमतों के प्रभावों को कम करने के लिए सोडा ऐश और एलएबीएसए की मात्रा कम करके अपने फॉर्मूलेशन में समायोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा, जब सोडा ऐश और एलएबी की कीमतें अपने चरम मूल्यों से कम हो गईं, हालाँकि कीमतें बढ़ने से पहले जितनी नहीं, तो डिटर्जेंट निर्माताओं ने अपने पुराने फॉर्मूलेशन को बहाल करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी सोडा ऐश और एलएबीएसए की मात्रा बढ़ा दी। इसलिए, प्राधिकरण डिटर्जेंट की कीमतों में कमी के रूप में कच्चे माल की कम कीमतों का संगत प्रभाव नहीं देख सका।

ढ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

129. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

i. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में बदलाव के कारण अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की है। इसलिए, गोपनीयता का दावा करने का तर्क वही रहेगा। 10/2018 के व्यापार नोटिस का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।

ii. यह याचिका 6 महीने के लिए दायर की गई थी, लेकिन प्राधिकरण ने उद्योग को हो रही क्षति के समाधान हेतु इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, यह जांच अवधि, पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3ए) के अनुरूप है।

iii. जुलाई-सितंबर 2023 तिमाही में निर्यातक देशों के सीमा शुल्क के अनुसार निर्यात मूल्य और भारतीय सीमा शुल्क के अनुसार आयात मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर था (जो निर्यात और आयात के बीच समय अंतराल के कारण हो सकता है)। इस प्रकार, जुलाई-सितंबर 2023 को शामिल करने से क्षति मार्जिन विकृत हो जाएगा।

iv. ग्वाटेमाला-सीमेंट II मामले में विश्व व्यापार संगठन ने पुष्टि की है कि प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद भी जांच अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जाँच शुरू करते समय भी जांच अवधि बढ़ाई जा सकती है।

v. कानून यह अनिवार्य नहीं करता कि जांच की शुरुआत की सूचना में छोटी अवधि के कारणों को दर्ज किया जाए। अनुच्छेद 12 के तहत, ये प्रारंभिक या अंतिम निष्कर्षों में दर्शाए जा सकते हैं। यह आवश्यकता केवल उन कारणों को दर्ज करने की है जिनके आधार पर छोटी अवधि का चयन किया गया है। इस प्रकार, यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक सूचना में या प्राधिकरण के विचाराधीन हो सकती है।

vi. प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2010-DGAD दिनांक 17.02.2012; और अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/3/2011-DGAD दिनांक 9.02.2013 में यह माना कि हल्का और सघन सोडा ऐश एक ही उत्पाद के दो रूप हैं। इसलिए, प्राकृतिक सोडा ऐश को भी PUC के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

vii. सघन और हल्के सोडा ऐश के बीच लागत का अंतर 5% से कम है, क्योंकि दोनों प्रकार के कई समान उपयोग हैं। उपभोक्ता दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा, सघन सोडा ऐश के आयात से हल्के सोडा ऐश के उत्पादन और बिक्री को भी नुकसान पहुँचा है।

viii. जैसा कि इच्छुक पक्षों ने दावा किया है, उत्पादन प्रक्रियाओं के संबंध में भी अलग पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय आयोग ने 10 अप्रैल 1995 के विनियमन (ईसी) संख्या 823/95 में यही बात कही है, जिसमें अमेरिका से आयातित डिसोडियम कार्बोनेट पर अनंतिम शुल्क लगाया गया है।

ix. इच्छुक पक्षों को गोपनीयता संबंधी दावे प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। इस समय-सीमा के भीतर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद कोई भी दावा समय-सीमा के अंतर्गत होगा।

x. जांच की अवधि में परिवर्तन के मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने 2018 के व्यापार नोटिस 10 के पूर्ण अनुपालन में संशोधित सूचना दाखिल की। इसके अलावा, आवेदन में दिए गए गोपनीयता तर्क को अद्यतन सूचना के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह तर्क सूचना के लिए समान रहेगा।

xi. घरेलू उद्योग ने 13 मई 2025 को संशोधित क्षति विवरण प्रसारित किया ' जिस पर भी पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद कोई टिप्पणी नहीं की गई।

xii. क्षति मार्जिन और मूल्य कटौती का निर्धारण करते समय उचित तुलना के एक तत्व के रूप में मालभाड़े को शामिल करना महत्वपूर्ण है। मालभाड़े पर विचार न करने से आयातित उत्पाद की कीमत और घरेलू उत्पाद की कीमत के बीच अनुचित तुलना हो जाएगी।

xiii. मान्यता देना विश्व व्यापार संगठन समझौते का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कम शुल्क नियम केवल एक सर्वोत्तम प्रयास खंड है और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए सदस्यों को पूर्ण विवेकाधिकार देता है।

xiv. 2003 में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर वार्ता समूह के समक्ष कम शुल्क नियम के अनिवार्य अनुप्रयोग पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दो वैकल्पिक विकल्प प्रस्तावित किए थे - एक मूल्य आधारित और दूसरा लक्ष्य मूल्य आधारित। किसी भी स्थिति में, क्षति मार्जिन का निर्धारण दो "मूल्यों" - घरेलू स्तर पर खरीदे गए उत्पाद की कीमत और आयातित उत्पाद की कीमत - के बीच के अंतर के रूप में किया जाना आवश्यक है।

xv. आयात मूल्य का अर्थ किसी भी स्तर पर आयात मूल्य हो सकता है, जैसे कि सीआईएफ, बंदरगाह मूल्य पर, आयातक के पुनर्विक्रय मूल्य पर या ग्राहक को वितरित मूल्य पर। इस प्रकार, आयात मूल्य और लक्ष्य मूल्य एक तुलनीय स्तर पर होने चाहिए।

xvi. वर्तमान में, निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग की फैक्ट्री-एक्स स्तर पर एनआईपी और बंदरगाह पर आयात मूल्य की तुलना कर रहे हैं। यदि आयात मूल्य बंदरगाह पर है, तो

यह फैक्ट्री-एक्स स्तर नहीं है; जबकि, घरेलू उद्योग की एनआईपी/कीमत फैक्ट्री-एक्स स्तर पर है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि सीमा शुल्क के भुगतान के बाद फैक्ट्री-एक्स स्तर पर एनआईपी और बंदरगाह पर आयात मूल्य तुलनीय स्तर/समान स्तर पर नहीं हैं। अन्यथा, तुलना प्रस्तावित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, जिसमें एक विकल्प आयात का सीआईएफ मूल्य हो सकता था।

xvii. इसलिए, भारत ने प्रस्ताव दिया था कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश आयातित उत्पाद की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत के साथ उपभोग के यथासंभव निकट से करें।

xviii. चूंकि भारत में डंपिंग रोधी शुल्क डंपिंग मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए मालभाड़ा सहित शुल्क से अत्यधिक संरक्षण नहीं मिलता, बल्कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से उचित तरीके से निपटने के लिए वर्तमान कार्यप्रणाली में विसंगति को ठीक किया जाता है।

xix. विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रस्ताव के अनुसार, "मूल्य" शब्द का अर्थ किसी भी स्तर पर आयात मूल्य के रूप में लगाया जा सकता है, जैसे लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ), या पूर्व-सीमा शुल्क क्षेत्र, या आयातकों को पुनर्विक्रय मूल्य, या ग्राहकों को वितरित मूल्य, बशर्ते कि क्षति मार्जिन पर पहुंचने के उद्देश्य से, डंप किए गए आयातों की कीमत के साथ तुलना केवल तुलनीय स्तर पर की जाए।

xx. पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पाद की मांग में मामूली वृद्धि हुई, तथापि, संबद्ध देशों से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अचानक और उल्लेखनीय रूप से 130% की वृद्धि हुई।

xxi. संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 130% की वृद्धि हुई तथा आधार वर्ष की तुलना में 86% की वृद्धि हुई।

xxii. देश में उत्पाद की सकल मांग लगभग 4.2 मिलियन मीट्रिक टन है जो देश में स्थापित क्षमता के बराबर है।

xxiii. सापेक्षिक दृष्टि से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयात आधार वर्ष में क्रमशः 17% और 14% था, जो जांच अवधि में बढ़कर 20% और 20% हो गया।

xxiv. सभी संबद्ध देशों से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है।

xxv. जांच अवधि में बिक्री लागत और विक्रय मूल्य में गिरावट आई। तथापि, जांच अवधि में विक्रय मूल्य में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक है। यद्यपि, संबद्ध आयात पिछले वर्ष तक दमनकारी/अवसादनकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहे थे, फिर भी वर्तमान पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और उत्पादन लागत दोनों से कम है।

xxvi. स्थिर क्षमता उपयोग के बावजूद, घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयातों में वृद्धि के कारण बिक्री और बाजार हिस्सेदारी खो दी, जिससे बढ़ते माल का प्रबंधन करने के लिए कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xxvii. उत्पादन को बनाए रखने और स्टॉक का प्रबंधन करने के लिए घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

xxviii. यद्यपि मांग बढ़ी, फिर भी आयात दोगुने से अधिक हो गया, जिससे बिक्री और राजस्व दोनों में भारी नुकसान हुआ।

xxix. बिक्री की मात्रा में कमी घरेलू उद्योग के साथ-साथ भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी परिलक्षित होती है, जिसमें जांच की अवधि में गिरावट आई, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।

xxx. जांच अवधि के दौरान, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी नीचे गिर गईं, जिससे बाजार कीमतों में भारी गिरावट आई। उत्पादन लागत में तो मामूली गिरावट आई, लेकिन बिक्री कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे लाभप्रदता में भारी गिरावट आई।

xxxi. 2022-23 में जब आयात कीमतें ज़्यादा थीं, तब घरेलू उद्योग ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालाँकि, उसके बाद से घरेलू उद्योग कम कीमत वाले आयातों के कारण तीव्र वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। जाँच अवधि में, लाभ और नकद लाभ दोनों में भारी गिरावट आई है।

xxxii. हालाँकि माँग बढ़ी, घरेलू उद्योग के भंडार में मामूली वृद्धि हुई। यह निर्यात के बावजूद है, जिसके बिना घरेलू उद्योग को ज़्यादा भंडार, कम उत्पादन और कम क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ता।

xxxiii. घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल रही है और जांच अवधि में मूल्य मापदंडों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

xxxiv. कीमतों में कटौती, घरेलू कीमतों में गिरावट, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट, कम कीमतों पर निर्यात, नकारात्मक वृद्धि और जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता, पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओआई में भारी कमी के कारण बढ़ते आयात पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुँचाई है।

xxxv. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की गणना करते समय आरएसपीएल और निरमा लिमिटेड के कैप्टिव उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए।

xxxvi. अनुबंध III के अनुसार, एनआईपी के निर्धारण के उद्देश्य से, नियम विभिन्न अवसरों पर केवल "उत्पादन" का उल्लेख करते हैं, बिक्री या कैप्टिव उपयोग के लिए उत्पादन के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। अनुबंध-II [पैरा (vi)] में आगे स्पष्ट रूप से "घरेलू उत्पादन" पर विचार करने का प्रावधान है। इसलिए, एनआईपी के निर्धारण के लिए "कैप्टिव उपयोग" के लिए उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कैप्टिव उत्पादन का उपयोग घरेलू उपभोग के लिए भी किया जाना है।

xxxvii. सोडा ऐश की कैप्टिव खपत को घरेलू खपत में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह या तो घरेलू बिक्री का विकल्प है या अन्य उत्पादकों द्वारा पूरी की जाती है। इस प्रकार, किसी भी स्थिति में, कैप्टिव उत्पादन की मात्रा को "घरेलू उत्पादन" में शामिल किया जाएगा।

xxxviii. आरएसपीएल की कैप्टिव खपत वास्तव में कैप्टिव बिक्री है, क्योंकि कंपनी इकाइयों के बीच चालान बनाए जाते हैं और भुगतान किया जाता है।

xxxix. ये आंतरिक बिक्री प्रचलित बाजार मूल्यों पर, लागू करों और जीएसटी के साथ, स्वतंत्र ग्राहकों को की गई बिक्री के समान की जाती है।

xl. आरएसपीएल के वित्तीय रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वास्तविक बिक्री हैं, न कि सामान्य कैप्टिव खपत, जिसमें कोई बिक्री या भुगतान शामिल नहीं होता।

xli. इस प्रकार, ये बिक्री न केवल बाजार मूल्य पर हो रही है, बल्कि बाहरी पक्ष को बिक्री के लिए लागू सभी वैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का भी पालन करती है। यदि यह कैप्टिव उपभोग होता, तो कोई बिक्री-खरीद नहीं होती और कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता।

xlii. टाटा केमिकल्स अपशिष्ट को समुद्र में नहीं बहाता, बल्कि कंपनी इसका उपयोग क्लिंकर सीमेंट बनाने में करती है। इस उत्पादन में हुए नुकसान को गैर-हानिकारक मूल्य से घटा दिया गया है। हालाँकि, सोडा ऐश निर्माण में अपशिष्ट जल का उपचार अपरिहार्य है, और इसे सीमेंट में परिवर्तित करना एक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार अनुपालन उपाय है, न कि एक अलग व्यवसाय।

xliii. इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी लागत या हानि मुख्य उत्पाद, यानी सोडा ऐश, के उत्पादन से आंतरिक रूप से जुड़ी होती है और इसे परिहार्य अक्षमताएँ या असंबंधित गतिविधियाँ नहीं माना जा सकता। ऐसी लागतों को बाहर करने से गैर-हानिकारक मूल्य कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा और कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं पर दंड लगेगा।

xliv. टाटा केमिकल्स लिमिटेड, अपशिष्ट जल को समुद्र में नहीं बहाती, बल्कि कंपनी उस अपशिष्ट जल का उपयोग क्लिंकर सीमेंट बनाने में करती है। इस उत्पादन में कंपनी को घाटा हो रहा है। इस घाटे को गैर-हानिकारक मूल्य से घटा दिया गया है।

xlv. वर्तमान जाँच में, जाँच अवधि के दौरान, कंपनी को इस पर घाटा हुआ है, क्योंकि व्यय अपशिष्ट के विक्रय मूल्य से अधिक है। अतः, उक्त लागत को रूपांतरण लागत का भाग माना जाना चाहिए।

xlvi. अपशिष्ट जल उपचार से क्लिंकर सीमेंट के उत्पादन में होने वाले नुकसान को एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III के तहत उत्पादन लागत में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अपशिष्ट जल उपचार विनिर्माण प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है। टाटा केमिकल्स द्वारा अपशिष्ट जल को सीमेंट में परिवर्तित करने का विकल्प एक अलग व्यावसायिक उद्यम नहीं है, बल्कि अनुपालन का एक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीका है। इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी लागत या हानि मुख्य उत्पाद, यानी सोडा ऐश के उत्पादन से आंतरिक रूप से जुड़ी होती है और इसे परिहार्य अक्षमताएँ या असंबंधित गतिविधियाँ नहीं माना जा सकता।

xlvii. टाटा केमिकल्स लिमिटेड के लिए डब्ल्यूआईपी को सभी चार वर्षों के लिए आनुपातिक आधार पर माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 के लिए प्रति इकाई आधार पर डब्ल्यूआईपी में उच्च नकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष में कच्चे माल की लागत सबसे कम रही, जिससे पीओआई में इस खाते पर उच्च मानकीकरण हुआ।

xlviii. सघन सोडा ऐश में कैप्टिव उपभोग के लिए सोडा ऐश की स्व-उपभोग की मात्रा को वर्तमान में विचाराधीन WIP आंकड़ों से घटाया जाना चाहिए। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रमाणीकरण भी प्रदान किया है।

ढ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

130. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात की गई टिप्पणियों की जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि ये टिप्पणियाँ, जो पुनरावृत्त हैं और जिनकी इस अंतिम निष्कर्ष के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पहले ही समुचित रूप से जाँच की जा चुकी है और जिनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है, संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात की गई जाँच में दोहराई नहीं जा रही हैं। हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए उन मुद्दों के अलावा, जिनकी विस्तार से जाँच की गई है और जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, नीचे उनकी जाँच की गई है।

131. यह तर्क कि बारह महीने से कम की प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) त्रुटिपूर्ण है, इसके चयन के अंतर्निहित तर्क को नजरअंदाज करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई, पाटन की मौजूदगी और उससे हुई क्षति, दोनों को स्थापित करने और फलस्वरूप ऐसी क्षति से निपटने के लिए शुल्क की उचित मात्रा, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस निष्कर्ष में दर्शाया गया है, अक्टूबर 2023 के बाद से आयात कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई, साथ ही आयात मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इस अवधि से पहले के महीनों को शामिल करने से निर्यातकों के वास्तविक पाटित और क्षतिकारी व्यवहार का पता नहीं चलता और इसलिए विश्लेषण विकृत हो जाता।

132. जबकि आवेदकों ने शुरू में छह महीने की जांच अवधि का प्रस्ताव रखा था, प्राधिकारी ने निर्यातक व्यवहार की व्यापक जाँच करने और अधिक व्यापक एवं संतुलित विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए इसे तीन महीने और बढ़ा दिया। यह दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं का समाधान करता है, साथ ही उस अवधि को भी दर्शाता है जिसमें वास्तव में पाटन और क्षति हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि एडीडी नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि जाँच शुरू करते समय जांच अवधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियम निर्दिष्ट प्राधिकारी को जाँच के दौरान आवश्यकतानुसार अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ-साथ घरेलू उद्योग से अनुपूरक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत करता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद भी जांच अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी का एकमात्र दायित्व और हितबद्ध पक्षों का अधिकार हितबद्ध पक्षों को बचाव का पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को ऐसा अवसर प्रदान किया है।

133. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि हितधारक पक्षों को प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, यह नोट किया जाता है कि आवेदन के अगोपनीय संस्करण को जांच की शुरुआत के चरण में प्रसारित किया गया था, जिसमें आवेदक की ओर से एक विशिष्ट परिशिष्ट शामिल था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि का हिस्सा क्यों नहीं माना जा सकता। इसके बाद, दो मौखिक सुनवाइयाँ हुईं, जिसके बाद हितधारक पक्षों द्वारा लिखित और प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दी गईं। इन कार्यवाहियों के दौरान, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में जुलाई-सितंबर 2023 को शामिल करने की अनुपयुक्तता पर अपनी स्थिति

दोहराई। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि हितधारक पक्षों को प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का पर्याप्त अवसर मिला।

134. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की छोटी अवधि अपनाने का औचित्य जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करते समय घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों की विधिवत जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि को जांच की अवधि में शामिल नहीं किया जाए। इसे केस फाइल में दर्ज किया गया है। जांच की शुरुआत की अधिसूचना में ऐसे कारणों को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल लिखित में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है और ऐसा ही किया गया है। इसके अतिरिक्त, जांच शुरू करने की सार्वजनिक सूचना में ऐसे कारण दर्ज करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 12 के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के चरण में, यदि कोई हो, या नियम 17 के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी करने के चरण में सार्वजनिक सूचना में ऐसे कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।

135. किसी भी स्थिति में , सार्वजनिक आरंभिक अधिसूचना में इन कारणों को शामिल न करने से किसी भी तरह से संबंधित पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जाँच अवधि के चयन का औचित्य जाँच के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और प्रकटीकरण विवरण के साथ-साथ इन अंतिम निष्कर्षों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए, प्राधिकारी एडीडी नियम 5(3 ए)(ii) के अंतर्गत आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुरूप है।

136. इस तर्क के संबंध में कि व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12.05.2004 के तहत निर्धारित क्षति अवधि का उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी को ऐसा कोई उल्लंघन नहीं

मिला। अक्टूबर 2023 से जांच अवधि शुरू करने की उपयुक्तता निर्धारित करने के बाद, प्राधिकारी ने उक्त व्यापार सूचना के प्रावधानों के अनुरूप, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2022-23) में शामिल कर लिया। इससे क्षति अवधि की निरंतरता सुनिश्चित हुई और क्षति अवधि के भीतर किसी भी अंतराल से बचा जा सका, जिससे व्यापार सूचना संख्या 2/2004 के साथ पूर्ण अनुरूपता बनी रही।

137. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि नियम 2(ख) यह अधिदेश देता है कि किसी निर्यातक से संबंधित घरेलू उत्पादक स्वतः ही अपात्र हो जाता है, प्राधिकारी को ऐसा दावा कानूनी आधारहीन लगता है। नियम 2(ख) प्राधिकारी को उन उत्पादकों को अपात्र घरेलू उत्पादक मानने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जिन्होंने स्वयं विषयगत वस्तुओं का आयात किया है, या जो विषयगत वस्तुओं के आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने टाटा केमिकल्स और निरमा लिमिटेड के संबंधित निर्यातकों की निर्यात मात्रा की जांच की। यह स्पष्ट किया जाता है कि टाटा केमिकल्स के संबंधित पक्षों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विषयगत वस्तुओं का निर्यात नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष अर्थात एसवीएम ने जांच की अवधि में स्वतंत्र ग्राहकों को सीधे *** मीट्रिक टन का निर्यात किया था। इसके अलावा, इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि को जानबूझकर छोटा किया गया था ताकि निरमा लिमिटेड के संबंधित पक्ष द्वारा किए गए निर्यात की अवधि को बाहर रखा जा सके, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, वास्तव में, अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि के दौरान ऐसे संबंधित निर्यातक द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया था। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि निरमा का ध्यान घरेलू बाजार में आयातित वस्तुओं को पेश करने पर नहीं है, न ही उसका संबंधित निर्यातक अपने निर्यात के माध्यम से भारतीय बाजार को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

138. हितबद्ध पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच की विस्तारित अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन/ वचनबद्धता/ घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन के साथ सभी घोषणाएं प्रस्तुत की थीं जो जांच प्रारंभ करने का आधार बनीं। यह नोट किया जाता है कि ये घोषणाएं सभी हितबद्ध पक्षकारों से ली गई हैं, और यह घोषणा जांच की पूरी अवधि के लिए वैध है, चाहे जांच की अवधि बाद में बढ़ाई जाए या नहीं । इन सत्यापनों/निरीक्षणों का उद्देश्य पक्षों द्वारा किए गए दावों की सटीकता की जांच करना और पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और सूचनाओं को प्रमाणित करना है। विस्तारित जांच की अवधि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणन प्रदान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आवेदन में आवश्यकताएं केवल आवेदन में प्रदान किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए हैं कि जहां लागू हो, डंपिंग, क्षति के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, और जहां लागू हो, ऐसे डंप किए गए आयातों और कथित क्षति के बीच एक कारण संबंध है, जो जांच शुरू करने का औचित्य साबित करता है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने साक्ष्यों से " *प्रथम दृष्टया " संतुष्ट* होने के बाद ही जाँच शुरू की । प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में शामिल संबंधित पक्षों के अभिलेखों का सत्यापन किया है। इस प्रकार, अब केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया जा सकता है।

139. के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संशोधित अगोपनीय सूचना विलंब से प्रस्तुत की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दूसरी मौखिक सुनवाई संशोधित आंकड़ों के प्रसारित होने के बाद ही आयोजित की गई थी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पक्षों को सुनवाई के दौरान और उनके लिखित एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के माध्यम से संशोधित सूचना पर अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। इन परिस्थितियों में, संशोधित प्रस्तुतियों के समय के कारण इच्छुक पक्षों द्वारा किसी पूर्वाग्रह का दावा उचित रूप से नहीं किया जा सकता है।

140. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में अंतर है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने की क्षमता है। इसके बावजूद, कुल मांग में आयात का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। यह नोट किया जाता है कि ऐसा घरेलू आपूर्ति में किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि भारी मात्रा में पाटित आयातों के कारण है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसे अपनी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेची जा रही कीमत से कम कीमत पर भी निर्यात की ओर मोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटित आयातों में वृद्धि के साथ ही जांच अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची में भी वृद्धि हुई है।

141. इस निवेदन के संबंध में कि आयात मूल्यों में अस्थायी गिरावट आयात मूल्यों में वास्तविक कमी के बजाय डाउनस्ट्रीम उत्पाद उद्योग में गड़बड़ी के कारण थी, यह नोट किया जाता है कि भारत में विषयगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, विदेशी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े निर्यात मूल्य की तुलना में घरेलू मूल्य में काफी अधिक दर्शाते हैं। इसलिए, कांच उद्योग में संभावित गड़बड़ी से भारत में विषयगत वस्तुओं की मांग प्रभावित नहीं हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि कांच उद्योग को एंटी-डंपिंग या प्रतिकारी शुल्कों के माध्यम से व्यापार उपचारात्मक उपाय के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि विषयगत वस्तुओं के अन्य प्रमुख उपभोक्ता, डिटर्जेंट उद्योग ने विषयगत वस्तुओं के आयात मूल्य में गिरावट के अनुसार मूल्य निर्धारण में कोई गिरावट नहीं दिखाई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि सोडा ऐश की कीमत में वृद्धि के साथ डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ीं, जबकि विषयगत वस्तुओं की कीमतों में कमी के साथ, डिटर्जेंट की कीमतों में कोई तदनुरूप कमी नहीं हुई।

142. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि विषयगत वस्तुओं का आयात 20,108 रुपये प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के अधीन है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी, यह ध्यान देने योग्य है कि उत्पाद के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) केवल 31 दिसंबर, 2025 तक ही है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एनआईपी वर्तमान में निर्धारित एमआईपी से बहुत अधिक है। यदि आयात न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) पर भी होता है, तो भी यह घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होगा। उत्पाद के डंप किए गए और हानिकारक आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए एमआईपी निर्धारित किया गया था। चूँकि न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) केवल 31 दिसंबर, 2025 तक ही प्रभावी है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए एमआईपी के विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार करते समय, वर्तमान में अनुशंसित एडीडी (पाटनरोधी शुल्क) पर विचार करेंगे।

143. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन जांच अवधि सहित संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान बढ़ा है, यह नोट किया जाता है कि हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई है, मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम हुआ है। इसके अलावा, जांच अवधि में उत्पादन में वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात बिक्री में गया। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा जांच अवधि में 19% से बढ़कर 27% हो गया, जो 8% की वृद्धि दर्शाता है, घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई हिस्सेदारी की लगभग समान हानि। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में भी यही पैटर्न उभरता है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों ने घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को अपने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है, इस प्रकार देश में पाटन के परिणामस्वरूप प्रतिकूल मूल्य प्रभाव स्थापित हुआ है।

144. इस तर्क के संबंध में कि एमआईपी ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया, यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारित एमआईपी उसकी क्षति-रहित कीमत से कम है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के आँकड़े दर्शाते हैं कि एमआईपी लागू होने के बावजूद, संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

145. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य, पीबीआईटी, मूल्यह्रास से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है, प्राधिकरण ने नोट किया कि विक्रय मूल्य, ब्याज और कर-पूर्व लाभ, और मूल्यह्रास जैसी जानकारी घरेलू उद्योग के मूल्य निर्धारण और लागत संरचना से संबंधित है, जो व्यवसाय-संवेदनशील जानकारी है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा इसे गोपनीय बताया गया था और प्राधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। इसलिए, इस वास्तविक जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता।

146. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश समान वस्तु नहीं हैं, प्राधिकारी ने पहले नोट किया था कि उपभोक्ता प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। हालांकि सोडा ऐश के दो रूपों को प्राप्त करने के स्रोत अलग-अलग हैं, हालांकि, दोनों स्रोतों से प्राप्त सोडा ऐश के तकनीकी और रासायनिक गुण और विनिमेयता में कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में समान हैं। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता उद्योग द्वारा उनका परस्पर उपयोग किया जाता है। प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2012 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/17/2020-डीजीएडी के तहत विषयगत वस्तुओं पर अपनी पिछली जांच में उल्लेख किया था कि अंतर उत्पादन प्रक्रिया प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश को असंबद्ध वस्तुओं के रूप में नहीं पेश कर सकती है

147. यह तर्क दिया गया है कि प्राकृतिक सोडा ऐश, सिंथेटिक सोडा ऐश की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन के कारण, पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ है। सिंथेटिक सोडा ऐश के बारे में दावा किया जाता है कि यह तीन गुना अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। इसके जवाब में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि कार्बन उत्सर्जन या पर्यावरणीय विशेषताओं में अंतर उत्पाद की मूल प्रकृति को नहीं बदलता है, न ही यह प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश के बीच अदला-बदली को प्रभावित करता है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि सोडा ऐश, चाहे वह किसी भी मूल का हो, डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो घरेलू नियामक प्रावधानों के अस्तित्व को इंगित करते हों जो एक प्रकार के दूसरे प्रकार के उपयोग को प्रतिबंधित या हतोत्साहित करते हों, या जो किसी विशेष प्रकार के सोडा ऐश को बढ़ावा देते हों।

148. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग के मूल्यह्रास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह ध्यान देने योग्य है कि जीएचसीएल ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है और इसके अतिरिक्त, आरएसपीएल, जो घरेलू उद्योग के अन्य घटकों की तुलना में बाजार में एक नई प्रवेशिका है, ने अपनी घरेलू बिक्री में वृद्धि की है। चूँकि मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर आबंटित किया गया है, इसलिए क्षति अवधि के दौरान मूल्यह्रास में वृद्धि देखी गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि जांच अवधि में प्रति इकाई नकद लाभ में वास्तव में गिरावट आई है ।

149. हितबद्ध पक्षों ने क्षति-रहित मूल्य की गणना के संबंध में विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी हैं। इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि 22% का प्रतिफल उचित नहीं है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उन्होंने लगातार 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की अनुमति दी है। हितबद्ध

पक्षों द्‌वारा इस पद्‌धति से विचलन का कोई औचित्य नहीं दिया गया है और इसीलिए वर्तमान जाँच में भी इसे अपनाया गया है।

150. यह तर्क कि कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी, यदि एडीडी लगाया जाता है तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ जाएँगी, त्रुटिपूर्ण है। संबंधित वस्तुओं की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर एडीडी का कोई भी प्रभाव न्यूनतम है और डाउनस्ट्रीम उत्पाद की सामर्थ्य को प्रभावित किए बिना इसे अवशोषित या हस्तांतरित किया जा सकता है।

151. जहां तक इस बात का प्रश्न है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड को उपयोगिता-संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा प्रभावित हुई और इसलिए माना गया जांच की अवधि उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्‌योग और विशेष रूप से टाटा केमिकल्स का उत्पादन जांच की अवधि में बढ़ा है। हितबद्‌ध पक्ष द्‌वारा संदर्भित सम्मेलन की प्रतिलिपि से यह भी पता चलता है कि यह कहा गया था कि बाजार कारकों के कारण प्रतिकूल मूल्य आंदोलन के बावजूद बिक्री की मात्रा में वृद्‌धि हुई है। इसी तरह, इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को उत्पादन में रुकावटों का सामना करना पड़ा, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्‌ध पक्ष द्‌वारा संदर्भित सम्मेलन की प्रतिलिपियों में से एक जांच की अवधि से पहले की है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्‌वारा सत्यापित जानकारी से पता चलता है कि जांच की अवधि में कोई असामान्य शटडाउन नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन खातों पर अन्य हितबद्‌ध पक्ष के दावों में कोई योग्यता नहीं है।

152. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कोविड-19, लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण तुलना अविश्वसनीय होने के तर्क के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि ये घटनाएँ जांच की अवधि से पहले के वर्षों में हुई थीं। वर्तमान जाँच में चयनित जांच की अवधि आधार वर्ष और पूर्व अवधियों के साथ एक सार्थक तुलना की अनुमति देती है। जांच की अवधि का चयन उपर्युक्त घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है। वास्तव में, यह देखा गया है कि जिन अवधियों में ये घटनाएँ हुईं, उनमें घरेलू उद्योग का प्रदर्शन जांच की अवधि की तुलना में बेहतर था, जो दर्शाता है कि इन घटनाओं का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन दर्शाते हैं।

153. ईटीआई सोडा और कज़ान के लिए पहुँच मूल्य की गणना के संबंध में, यह नोट किया गया है कि निर्यात मूल्य के समायोजन के दावे बिना साक्ष्य के प्रस्तुत किए गए थे। सीआईएफ, सीएफआर और एफओबी मूल्य से निर्यात मूल्य निकालने के लिए, माल ढुलाई और अन्य बंदरगाह और हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल ढुलाई और बीमा पर विचार किया जाना है। हालाँकि, इस संबंध में किसी भी जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने ईटीआई सोडा और कज़ान के अन्य संबंधित पक्षों के लिए समायोजन के औसत मूल्य पर विचार किया, जिसके लिए साक्ष्य उपलब्ध थे। सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखते हुए पहुँच मूल्य की गणना की गई है। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पहुँच मूल्य और प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दावा किए गए आंकड़े के बीच का अंतर इन समायोजनों के विचार के कारण है।

154. इस तर्क के संबंध में कि डिटर्जेंट आपूर्तिकर्ता सीमित मार्जिन पर काम करते हैं और शुल्क लगाने से लागत बढ़ेगी, भारत के डिटर्जेंट क्षेत्र के लिए सोडा ऐश आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, और अंततः अंतिम उपभोक्ता पर 3.49% प्रभाव पड़ेगा, यह ध्यान दिया जाता है कि घरेलू उद्योग में उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

वास्तव में, ऐसी मांग का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा रहा है । तदनुसार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) के प्रभाव और, विस्तार से, उपभोक्ताओं पर, आनुपातिक रूप से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि खरीद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसे शुल्क के भुगतान के बिना किया जाता है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रभाव विश्लेषण में बढ़ी हुई लागत पर 20% लाभ मार्जिन शामिल है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ इस अनुमानित मार्जिन से काफी कम है

155. तुर्की सरकार ने दावा किया है कि प्रकटीकरण विवरण में विषयगत देश के दायरे में यूएई को शामिल करना कानूनी आधार के बिना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विषयगत देश ईरान है। प्राधिकारी ने आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है कि ईरान में उत्पन्न होने वाले माल को यूएई द्वारा ट्रांसशिप किया जा रहा है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि आईएचएस मार्किट रिपोर्ट, दिसंबर, 2020 से ग्लोबल सोडा ऐश मासिक रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, जो दर्शाता है कि यूएई में वास्तव में सोडा ऐश के उत्पादक नहीं हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वास्तव में यूएई के माध्यम से आने वाले आयात वास्तव में ईरानी मूल के सोडा ऐश हैं। प्राधिकारी ने आवेदक कंपनियों में से एक द्वारा भेजे गए आईएचएस मार्किट कार्मिक के ईमेल संचार को भी नोट किया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यूएई में उत्पादक नहीं हैं और केवल ईरानी उत्पादों को रूट किया जाता है।

156. घरेलू उद्योग ने क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय मालभाड़े को शामिल करने के अपने दावे को दोहराया है। प्राधिकरण अपने इस निर्णय को कायम रखते हैं कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय, बिना मालभाड़े के उतराई मूल्य की तुलना एनआईपी के साथ समान स्तर पर करना प्राधिकरण की सतत प्रथा है। इस मामले में भी यही पद्धति अपनाई गई है।

157. टाटा केमिकल्स के लिए डब्ल्यूआईपी में परिवर्तन पर विचार करने संबंधी चिंता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण की सतत प्रथा के अनुसार, घरेलू उत्पादक द्वारा डब्ल्यूआईपी पर विचार हेतु दी गई सूचना पर एनआईपी निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस दावे के संबंध में कि सघन सोडा ऐश में कैप्टिव उपभोग के लिए सोडा ऐश के स्व-उपभोग को डब्ल्यूआईपी आंकड़ों से घटाया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करते हैं कि प्रकटीकरण जारी होने के बाद पहली बार इस तरह का अनुरोध उनके ध्यान में लाया गया है। इस प्रकार, इस दावे का सत्यापन नहीं किया जा सका।

158. इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी का निर्धारण करते समय कैप्टिव खपत पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि प्रत्येक आवेदक की एनआईपी के साथ-साथ समग्र रूप से आवेदकों की भारित औसत एनआईपी की गणना प्राधिकरण द्वारा लगातार अपनाई गई पद्धति के अनुसार की गई है।

159. इस दावे के संबंध में कि क्लिंकर उत्पादन में टाटा केमिकल्स द्वारा उठाए गए नुकसान को अनुबंध III के अंतर्गत लागत का निर्धारण करते समय शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि क्लिंकर और सीमेंट के नुकसान के लिए दावा की गई लागत को विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनपीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त अपशिष्ट पदार्थ/स्क्रैप एनपीयूसी के लिए कच्चा माल बन गया। इस प्रकार, इस मद में कोई भी नुकसान एनपीयूसी से संबंधित है।

ण. <u>निष्कर्ष और सिफारिश</u>

160. प्रस्तुत किए गए निवेदनों और उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर; तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

i) विचाराधीन उत्पाद का दायरा रूस, ईरान, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" है।

ii) विषयगत वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत कोड 283620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

iii) प्राधिकरण ने प्राकृतिक सोडा ऐश के बहिष्करण अनुरोध और सघन एवं हल्के सोडा ऐश के लिए पीसीएन पद्धति अपनाने से संबंधित प्रस्तुतियों की जाँच की है। तदनुसार, अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी और इस प्राधिकरण के पिछले निर्धारणों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान जाँच में बहिष्करण अनुरोध और पीसीएन पद्धति के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। कारण अज्ञात

iv) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से आयातित की जा रही विषयगत वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

v) यह आवेदन अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर किया गया है। वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले उत्पादक मेसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मेसर्स निरमा लिमिटेड, मेसर्स आरएसपीएल लिमिटेड, मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स जीएचसीएल लिमिटेड हैं।

vi) मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड और मेसर्स निरमा लिमिटेड, दोनों का अमेरिका में एक-एक संबंधित निर्यातक है। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान उनसे निर्यात की मात्रा का सत्यापन किया गया। मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, यह पाया गया कि जांच की अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ। मेसर्स निरमा लिमिटेड के मामले में, जांच की अवधि में निर्यात सीधे अंतिम ग्राहक को किया गया था, इसके अलावा, यह मात्रा मेसर्स निरमा लिमिटेड के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ भारत में कुल आयात के संदर्भ में

नगण्य थी। इस प्रकार, नियम 2(ख) के अनुसार उत्पादकों को पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है।

vii) रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंड को पूरा करता है।

viii) हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों का विरोध किया गया। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा अनुवर्ती संशोधन के बाद, प्राधिकारी उनके दावों से संतुष्ट हैं । तदनुसार, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।

ix) घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच में 6 महीने की अवधि को जाँच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया था और अप्रैल-सितंबर 2023 को जाँच अवधि के भाग के रूप में न मानने के कारण प्रस्तुत किए थे क्योंकि यह पाटित आयातों से होने वाली क्षति को प्रतिबिंबित नहीं करता था। प्रस्तुत तर्क उचित पाया गया, तथापि, क्षति पहुँचाने वाले पाटन के व्यापक विश्लेषण के लिए जाँच में 9 महीने की जाँच अवधि को उपयुक्त माना गया है।

x) सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन, साथ ही गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर निर्धारित मार्जिन, नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर हैं।

xi) विचाराधीन उत्पाद को भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर और महत्वपूर्ण है।

xii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझा है।

xiii) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई।

xiv) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध आयातों में 86% की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में यह दोगुना हो गया है। सापेक्षिक दृष्टि से भी जांच अवधि में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

xv) आयात मूल्य और घरेलू उद्योग की कीमतों के विश्लेषण से पता चलता है कि मूल्य में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है ।

xvi) हालाँकि पहले बिक्री मूल्य लागत से ज़्यादा बढ़े थे। लेकिन, जाँच अवधि के दौरान, बिक्री मूल्य लागत की तुलना में अनुपातहीन रूप से गिर गए। इसके साथ ही, घरेलू उद्योग को भी कीमतों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है।

xvii) प्राधिकरण ने भौतिक क्षति के आकलन हेतु प्रासंगिक सभी आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जाँच की है। विश्लेषण से पता चलता है कि क्षति जाँच अवधि के दौरान भारत में सोडा ऐश की माँग में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग को उसके अनुरूप लाभ नहीं मिल पाया है। इसके बजाय, उसे बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट, लाभप्रदता और निवेश पर लाभ में गिरावट, माल-सूची में वृद्धि और नकदी प्रवाह में कमी का सामना करना पड़ा है।

xviii) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिग्रस्त कीमत और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करने पर यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।

xix) गैर-आरोपण विश्लेषण से पता चलता है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथा उसे पाटित आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है।

xx) प्राधिकरण को घरेलू उद्योग की सुरक्षा, उपभोक्ता और जनहित में संतुलन बनाए रखते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग उपाय आवश्यक लगते हैं। यह पाया गया है कि एडीडी का डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंततः अंतिम उपभोक्ता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

161. पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच आरंभ करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की भरपाई के

लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी, विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

162. अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विषयगत देशों में मूल की या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और विषयगत देशों में मूल की या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

एस. एन.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	2836.20	सोडा ऐश (डिसोडियम कार्बोनेट)	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान सहित कोई भी देश	ईटीआई सोडा यूरेटिम पज़ारलामा नकलियत वे इलेक्ट्रिक यूरेटिम सनायी वे टिकारेट ए.एस.	69	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
					मैसर्स कज़ान सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.			
2.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान सहित	तुर्की सिस और कैम फैब्रिकालारी अनाम सिरकेटी	17	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

				कोई भी देश				
3.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की सहित कोई भी देश	एसएन 1 और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	113	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
4.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	तुर्की	कोई	113	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
5.	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बश्किर सोडा कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेरेज़्निकी सोडा फैक्ट्री	40	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
6.	-वही-	-वही-	रूस	रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान सहित कोई भी देश	एसएन 5 के अलावा कोई भी निर्माता	89	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
7.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई	89	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
8.	-वही-	-वही-	यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	सिसेकैम व्योमिंग एलएलसी	27	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

9.	-वही-	-वही-	यूएसए	रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान सहित कोई भी देश	एसएन 8 के अलावा कोई भी निर्माता	79	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
10.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	यूएसए	कोई	79	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
11.	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान सहित कोई भी देश	कोई	88	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
12.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	ईरान	कोई	88	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

नोट: यदि आयात संयुक्त अरब अमीरात से होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी विषयगत वस्तुओं के मूल का सत्यापन कर सकते हैं।

त. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

163. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी